• वर्ष-2
• अंक-238
रायपुर, शनिवार 27 मई 2023
• पृष्ठ-6
• मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

नए संसद भवन को लेकर दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, हर्जाना लगाते हुए खारिज क्यों नहीं करना चाहिए

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। जहां नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देता दिखा। वहीं पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिल गई है। हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी हो गए। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 22 मई से 26 मई 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत की प्रथम नागरिक और संस्था के प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं, हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस जे के माहेश्वरी और पी एस नरसिम्हा की बेंच के सामने यह मामला लगा. जजों ने शुरू में ही पूछा कि इस तरह की याचिका को हर्जाना लगाते हुए खारिज क्यों नहीं करना चाहिए? इस पर वकील ने अपनी बात रखने की अनुमति मांगी. जजों ने उनसे कहा कि आप अपनी बात रखिए.

याचिकाकर्ता ने कहा कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं. संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का जो गठन बताया गया है, उसके तीन हिस्से

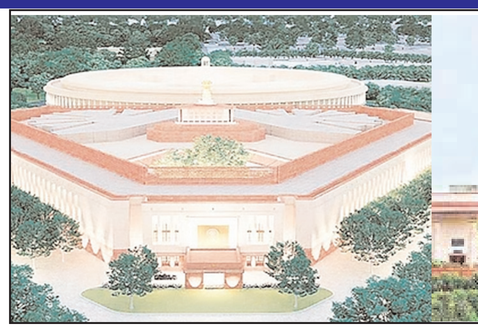

हैं - राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा. इस तरह राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है जबकि प्रधानमंत्री सिर्फ संसद के सदस्य हैं. इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, अनुच्छेद 79 सिर्फ एक व्यवस्था की व्याख्या करता है. इसमें कहीं भी इस बात की अनिवार्यता नहीं दी गई है कि कोई उद्घाटन भी राष्ट्रपति के हाथों ही करवाना जरूरी है.

अनुच्छेद 32 के तहत कैसे दाखिल की गई

जस्टिस जे के माहेश्वरी में इस बात पर आश्चर्य जताया कि इस तरह की याचिका अनुच्छेद 32 के तहत कैसे दाखिल की गई है? मामले में याचिकाकर्ता या किसी भी व्यक्ति का कौन सा अधिकार प्रभावित हो रहा है? वकील ने एक बार फिर कहा की अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं और 87 के तहत वह दोनों सदनों को संबोधित करते हैं. आखिरकार जजों ने कहा, हमने याचिकाकर्ता को काफी देर तक अपनी बात रखने की अनुमति दी वह यह साबित नहीं कर पा रहा है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना चाहिए? संविधान के जिन अनुच्छेदों का उल्लेख उन्होंने किया, उनसे कहीं भी यह साबित नहीं होता कि किसी इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए.इसके बाद जजों ने याचिका खारिज करने का आदेश लिखवाना शुरू किया. तब याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. कोर्ट में मौजूद सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि अगर याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई तो याचिकाकर्ता इसे हाई कोर्ट में दाखिल कर देगा. इस पर जजों ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहता है. वकील ने इससे मना किया. इसके बाद कोर्ट ने उसे याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.

पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से मिली राहत

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और तीन साल के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया। न्यायाधीश ने गांधी के वकील से कहा कि मैं आंशिक रूप से आपके आवेदन की अनुमति दे रहा हूं। 10 साल के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए। बता दें कि राहुल गांधी ने एक सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मांगी थी। गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी हैं जिसमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। शुक्रवार की सुबह अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि- केलंबित सारे मुकदमों की अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा सुनवाई

नईदिल्ली। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेग। हाई कोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत में वर्तमान में चल रहे मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। हाई कोर्ट ने 3 मई को मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हिंदू भक्तों ने मथुरा जिला अदालत से उच्च न्यायालय तक उस भूमि पर अधिकार का दावा किया है, जिस पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है ।याचिका में कहा गया था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान द्वारा कटरा केशव देव खेवत मथुरा में रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य लोगों और प्रतिवादियों के वकील के माध्यम से दायर की गई थी। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा मामले में प्रतिवादी हैं ।आवेदकों ने ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समुदाय के अधिकार का दावा करते हुए घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि इसका निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था और इस तरह का निर्माण मस्जिद नहीं हो सकता क्योंकि कोई वक्फ कभी नहीं था। बनाया था। याचिका में कहा गया है कि जमीन कभी भी मस्जिद के निर्माण के लिए समर्पित नहीं की गई थी।

इन दिनों

✍ नरेन्द्र नाथ

मध्यवर्ग से राजनीतिक पार्टियों की बेरूखी

देश की राजनीति में मध्यवर्ग का बड़ा योगदान माना जाता रहा है। मुल्क की सियासत का नैरेटिव तय करने और उसे दिशा देने में इस तबके को सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। पहले कई मौकों पर मध्यवर्ग ने इसे साबित भी किया है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से यह अपनी सियासी पूंजी गंवाता हुआ दिख रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हाल के दिनों में मध्यवर्ग किसी की भी प्राथमिकता में नहीं दिख रही है। आखिर इस ट्रेंड के पीछे क्या वजह है? जानकार जल्दबाजी में इसे लेकर कोई राय नहीं बनाना चाहते, लेकिन इतना वे भी मानते हैं कि इधर राजनीतिक दलों की ओर से पेश किए जाने वाले सियासी मेन्यू में मध्यवर्ग के स्वाद का खयाल नहीं रखा जा रहा है। उदारीकरण के बाद नब्बे के दशक से मध्यवर्ग का राजनीति में दखल बढ़ा है। खासकर नैरेटिव बनाने में इस तबके की सबसे अहम भूमिका मानी जाने लगी थी। लेकिन यह बात भी सामने आई कि पिछले कुछ वर्षों में इस तबके को सरकार से अपेक्षा के मुताबिक सौगात नहीं मिली। वैसे इस बारे में सरकार का दावा है कि मध्यवर्गीय लोग उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। लेकिन मध्यवर्गीय लोग शायद ही इससे इत्तेफाक रखें। सच यह भी है कि मध्यवर्ग की अनदेखी की वजह हालिया सियासी नतीजे भी हो सकते हैं। बजट से लेकर चुनावी वादों तक, हाल के दिनों में आए तमाम राजनीतिक परिणामों में यह बात समान रूप से दिखी कि राजनीतिक दल गरीब और किसानों पर अधिक फोकस करते रहे हैं। गांव की आबादी उनकी प्राथमिकता में रही है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावों में गांव में रहने वाले लोग, गरीब और किसान राजनीतिक दिशा तय करने में कहीं अधिक भूमिका निभाते रहे हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने इनके लिए कई योजनाएं लॉन्च कीं और इस तबके के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी भी है। सरकार ने इन पर लगातार फोकस किया। केंद्र के अधिकतर संसाधन किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के संचालन में गए। इसका सियासी लाभ भी उन्हें मिला। लेकिन इस हिसाब से मध्यवर्ग को सौगातें नहीं मिलीं। यह भी सही है कि सीमित आर्थिक संसाधनों में सरकार हर तबके को खुश नहीं रख सकती। वह भी तब, जब पिछले कुछ वर्षों से देश की आर्थिक दशा वैसी मजबूत नहीं रही। वैसे इसका एक और पहलू है। सत्ता पक्ष का यह तर्क है कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई ऐसे कदम उठाए, जिनका अप्रत्यक्ष लाभ मध्यवर्ग को मिला है। सरकार से जुड़े एक सीनियर नेता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया गया। सड़क और रेल सेवा बेहतर की गई। इन तमाम चीजों से सबसे अधिक लाभ मध्यवर्गीय आबादी को ही होता है। उनका तर्क था कि मिडल क्लास को सीधा लाभ देने से बेहतर है उसे बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना। सरकार ऐसा कर रही है और उसका लाभ भी इस वर्ग को मिल रहा है। उधर, विपक्ष ने भी गरीब और गांव में रहने वालों पर ही फोकस किया और उन्हें चुनावों में मुफ्त की चीजें देने का एलान किया। इसका लाभ भी उसे मिला। ऐसे में संदेश यह भी गया कि दोनों पक्ष इस सोच के साथ आगे बढ़े कि मध्यवर्ग और शहरी आबादी को कुछ समय के लिए नाराज करने का राजनीतिक जोखिम लिया जा सकता है।

नईदिल्ली। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने 20 मई को आठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ क्रमशः कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की है।

सेंगोल धर्म और न्यायप्रणाली का प्रतीक : स्मृति

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस सहित लगभग 21 दलों ने इसके बहिष्कार का फैसला लिया है। इन सब के बीच सेंगोल को इस बार संसद भवन में लगाया जाएगा। इसको लेकर भी आप राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां इसको लेकर सवाल उठाए तो ही भाजपा अब उस पर पलटवार कर रही है। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सेंगोल का अपमान भारतीय इतिहास का अपमान है। उन्होंने कहा कि संकुल परिवर्तन का प्रतीक है। कांग्रेस हताश

■ गांधी परिवार ने इसे सिर्फ छड़ी के रूप में देखा

होकर आरोप लगा रही है। सेंगोल भारतीय इतिहास का विशिष्ट अंग है। लेकिन गांधी परिवार ने हमेशा इसे एक छड़ी के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि संघ और धर्म और न्याय प्रणाली का भी प्रतीक है ।संसद के उद्घाटन पर कांग्रेस के बहिष्कार पर कि उन्होंने तंज कसा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का विरोध स्वाभाविक है। उनके लिए राजनीति का मतलब परिवारनीति है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार देशवासियों का अपमान है। राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस नेताओं ने क्या-क्या नहीं कहा। आज कांग्रेस राष्ट्रपति की दुहाई क्यों दे रही है? केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि नई संसद का उद्घाटन देश का कार्यक्रम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस महादेव और नंदी के विरोध में है? क्या कांग्रेस मानती है कि वह हिंदू विरोधी पार्टी है? इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किए जाने वाले रस्मी 'राजदंड' के महत्व को कमतर करके ''चलते समय सहारा देने के काम आने वाली छड़ी'' बना देने का आरोप लगाया तथा सवाल किया कि उसे भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को दावा किया कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 'राजदंड' को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित किये जाने का प्रतीक बताया हो।

प्रमुख समाचार

भूपेश का दावा, 2024 में यूपीए की आएंगी 300+ सीटें

नयी दिल्ली। लोकसभा चुनाव में साल भर का वक्त शेष रह गया है। लेकिन चुनावी दल अभी से इलेक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी की तरफ से अपनी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तमाम तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दावा कर दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नीत यूपीए को 300 से अधिक सीटें आएंगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें हासिल हुई थी। जबकि कांग्रेस की तरफ से 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। छत्तीसगढ़ की 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। राज्य की बस्तर और कोरबा लोकसभा सीटों के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे केजरीवाल-मान

नयी दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाये गये अध्यादेश के जरिये नौकरशाही पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार के नियंत्रण को वापस ले लिया गया है। इससे पहले, दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है। आप शासित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

NITI Aayog

झूठे वादों पर भाजपा ने खड़ी की 9 साल की इमारत-राहुल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल पूरे होने पर भाजपा जहां प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों की बखान कर रही है। तो वहीं कांग्रेस जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमला किया है। इन सब के बीच आज कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया और उनसे 9 सवाल पूछे गए। इन्हीं सवालों को लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने दिखाकर झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी की 9 साल की इमारत! राहुल गांधी ने कांग्रेस के 9 सवाल वाले पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि महंगाई, नफ़रत और बेरोज़गारी- प्रधानमंत्री जी, अपनी इन नाकामियों की लीजिए ज़िम्मेदारी।

कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर पेंच फंसा

नयी दिल्ली। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने 20 मई को आठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ क्रमशः कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि शुरूआती योजना के तहत मंत्रिमंडल में करीब 28 विधायकों को शामिल किया जाना था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की है। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट बनाने और कैबिनेट में किसे शामिल करने का फैसला मुख्यमंत्री का है। सिद्धारमैया ने पार्टी के साथ विभिन्न नामों पर चर्चा की है, हमने अब इसे तय करने के लिए उन पर छोड़ दिया है। मुझे उनके (सिद्धारमैया) द्वारा बताया गया था कि कर्नाटक में कल और विस्तारित मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा।

आतंकी मामले में यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग

नयी दिल्ली। नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख और कश्मीरी आतंकवादी से अलगाववादी बने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। मलिक को इससे पहले निचली अदालत ने एक आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मलिक ने 10 मई को अदालत से कहा था कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की खिलाफत नहीं कर रहा है, जिसमें धारा 16 , 17 , 18 और 20 और आईपीसी की धारा 120-बी और 124-ए (राजद्रोह) शामिल हैं। इससे पहले अदालत ने फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा महराजुद्दीन, कलवाल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल रशीद शेख और नवल किशोर कपूर सहित कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए।

संसद भवन पर मची रार

भाजपा का दांव चल गया विपक्ष, दलित-आदिवासी मुददे पर लगेगी नैया पार?

जितेंद्र भारद्वाज

संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार मची हुई है। दोनों के बीच पनपा गतिरोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगभग 19 राजनीतिक दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। विपक्ष का कहना है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को समारोह में न बुलाकर भाजपा ने लोकतंत्र का अपमान किया है। साथ ही इस मामले में विपक्षी दलों ने भाजपा का दांव, भाजपा पर ही चल दिया है। विपक्षी दलों ने कहा, जब संसद के नए परिसर का भूमि पूजन किया गया, तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। भाजपा ने कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर यह बताने का प्रयास किया था कि वह दलित समाज के हितों का कितना ख्याल रखती है। इसके बाद जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनीं, तो भाजपा ने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का खूब प्रचार किया था। उस वक्त इन दोनों बातों को भाजपा का चुनावी दांव बताया गया। अब राहुल से लेकर केजरीवाल तक ने उसी दांव को भाजपा के खिलाफ चल दिया है। जानकारों का यह भी कहना है कि विपक्षी नेता दलित-आदिवासी नाव में सवार हो कर 2024 देख रहे हैं।

ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के

प्रमुख शिवाजीराव मोघे ने तो यहां तक कह दिया कि संसद भवन के उद्घाटन पर देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं करना, देश के समस्त आदिवासियों का अपमान है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आदिवासी कांग्रेस ने शुक्रवार को कई राज्यों में प्रदर्शन किया है। उन्होंने तकरीबन वे सभी बातें दोहरा दीं, जो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भाजपा की तरफ से कही गई थीं। भाजपा ने अपने इस कदम से लोकतंत्र को अपमानित किया है। मोघे ने साफतौर पर कहा, मैं नहीं जानता कि क्या यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि हम आदिवासी हैं। विपक्षी दलों ने भी अपने संयुक्त बयान में कहा, नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को न बुलाकर मोदी सरकार ने संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही निकाल दिया है।

2017 में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, तो भाजपा ने उसे खूब भुनाया था। जब राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनकी उम्मीदवारी का एलान हुआ तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कई बार %दलित% शब्द का इस्तेमाल किया था। भाजपा, कोविंद के नाम को इतने एग्रेसिव तरीके से लोगों के बीच ले गई कि विपक्ष को भी दलित समाज से आने वाली मीरा कुमार का नाम आगे करना पड़ा। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा भी मिला। गत वर्ष जब द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति बनीं तो भाजपा ने उन्हें पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का प्रचार प्रसार किया था। यहां तक कि जब कांग्रेस और भाजपा के बीच किसी मुद्दे पर तकरार हुई तो भाजपा ने कहा, कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पर आसीन हुई हैं। भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व ने सार्वजनिक मंचों से यह बात कही। तब भी विपक्षी नेताओं ने दबी जुबान में कहा था कि ये सब 2024 के चुनाव में आदिवासी वोट लेने का एजेंडा है।

संसद के नए भवन के उद्घाटन पर अब विपक्ष ने भाजपा का वही दांव भाजपा पर ही चल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, संसद संवैधानिक मूल्यों से बनती है, न कि अहंकार की ईंटों से। संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नहीं कराया जाना और समारोह में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाना, यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। इसके बाद कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों न कराना, देश के सभी आदिवासियों का अपमान है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाकर भाजपा ने आदिवासियों और दलित समुदायों का अपमान किया है। राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। संसद भवन के शिलान्यास पर भी रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन पर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुला रहे। देशभर की अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां पूछ रही हैं कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया जा रहा।

कांग्रेस सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार और घोटाला कर रही : केदार कश्यप

■ भाजपा मडंल बेलरगांव की कार्यसमिति बैठक संपन्न

नगरी। भाजपा मडंल बेलरगांव का कार्यसमिति बैठक आयोजित किया गया। ग्राम बिरगुड़ी के हल्बा समाज भवन में जिसमें बूथ सशक्तिकरण एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया जिसमें बैठक में विशेष रूप से बैठक प्रभारी पूर्व मंत्री एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा केदार कश्यप,सिहावा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बस्तर महाराजा कमलचन्द्र भंजदेव, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, किसान मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री पिंकी शाह,पूर्व विधायक सिहावा श्रवण मरकाम, जिला महामंत्री एवं बेलरगांव मंडल प्रभारी प्रकाश बैस, जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी, मंडल अध्यक्ष अकबर कश्यप उपस्थित थे।

जिसमें बैठक प्रभारी पूर्व मंत्री एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा केदार कश्यप ने कहा कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार और घोटाला कर रही हैं।भाजपा की एक-एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि सरकार के भ्रष्टाचार को घर - घर व गांव-गांव पहुंचकर लोगों को बताएं?। आप सभी कार्यक्रर्ता प्रत्येक बूथों में चार से पांच दिन रोजाना जाएं अब चुनाव नजदीक है हम सब अभी से लग जाए ओर नये मतदाताओं का स्वागत करें।

सिहावा विधानसभा प्रभारी कमलचंद भंजदेव ने कहा कि जब से प्रदेश में भूपेश की सरकार बनी है किसान, मजदूर, आम जनता, छात्र,युवा एवं सभी वर्गों के लोग त्रस्त हो चुके हैं। गौठानों के नाम पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता एक एक गौठानों में जाकर राज्य सरकार की इस भ्रष्टाचार को उजागर करे। मंडल अध्यक्ष अकबर कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना रोककर कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही हैं।

उक्त बैठक में मुख्य रूप से मंडल महामंत्री मनोहर मानिकपुरी, राकेश चौबे,पूर्व जिला महामंत्री नागेन्द्र शुक्ला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल डागा,मीडिया प्रभारी रामगोपाल साहू,सासंद प्रतिनिधि जनपद पंचायत नगरी मोहन पुजारी, जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव, जनपद उपाध्यक्ष हुमित लिमजा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र नेताम, रूपदास मरकाम विस्तारक सिहावा विधानसभा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मौर्यधवज सेन, युवा मोर्चा महामंत्री चुम्मन साहु, लिलेश प्रजापति, उपाध्यक्ष दीपक साहु, मोनू साहु,मंडल मंत्री विनय देवागंन,वैदकुमार गंजीर,पूर्व मंडल अध्यक्ष शेखर अडिल,पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्यवती नेताम, पूर्व जनपद सदस्य अजय ध्रुव, टिकेश्वर ध्रुव, गनेशिया मरकाम, मनोहर सोनवानी, उमेंश साहु, गौचंद मरकाम, डाकेंद्र कश्यप, संजय शाडिलय, भुवनदास मानिकपुरी, डा.के.एस शाडिलय, सुकचंद मरकाम, बिसरी कुजांम, अनिता मरकाम, मोहित जैन,सोहन साहु, चैनसिंह पटेल, राकेश बिसेन, अर्जुन देवागंन, रामप्रसाद मरकाम, भूषण देवागंन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर भाजपा की सरकार बनाना है : कमलचन्द्र भंजदेव

नगरी। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा संगठन महामंत्री केदार कश्यप व सिहावा विधानसभा प्रभारी बस्तर महाराजा कमलचंद्र भंजदेव, किसान मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती पिंकी शिवराज शाह व अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने सिहावा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर मंडलों में कार्यसमिति की बैठक ली। सुबह 11 बजे बेलरगांव मण्डल की बैठक हल्बा समाज भवन बिरगुड़ी में, दोपहर 1 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेता स्व. गुलजार सिंह मरकाम के परिवार से मुलाकात किये। दोपहर 2 बजे नगरी मंडल की बैठक मानस भवन सांकरा में लिये। शाम 4:00 बजे कुकरेल मंडल की बैठक साहू भवन कुकरेल में लिये। उसके पश्चात शाम 5:00 बजे कोर कमेटी की बैठक रेस्ट हाउस बनरौद में संपन्न हुआ। सिहावा विधानसभा प्रभारी बस्तर महाराज भंजदेव ने कहा कि अब समय आ गया है वक्त के साथ दौड़ने का। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर अगली बार भाजपा की सरकार बनाना है। बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए तत्परता दिखाएं। प्रदेश संगठन महामंत्री केदार कश्यप ने मंडलों के पदाधिकारियों की गिनती करते हुए कहा कि जिन्होंने पद धारण किया है उन्हें तन मन से काम करना होगा। यदि कोई काम करने में सक्षम नहीं है तो वह स्वयं दूसरे को मौका दें। कोर कमेटी की बैठक में केदार कश्यप ने कहा कि कार्यकर्ताओं को तन मन लगाकर संगठन के लिए काम करना होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा तभी हम भाजपा की सरकार बना पाएंगे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, पूर्व विधायक सिहावा श्रवण मरकाम, जिला महामंत्री प्रकाश बैस, जिला उपाध्यक्ष नरेश सिन्हा, जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी, रविशंकर दुबे, विकल गुप्ता आदि उपस्थित थे।

चलबो गौठान खोलबो पोल, कार्यक्रम के तहत बरपाली गौठान का किया दौरा

कोरबा। भूपेश बघेल ने गोठान के नाम पर सरपंचों पर दबाव बनाकर केंद्र सरकार की राशि 15 वी वृत्त की राशि मूलभूत की राशि' और 'मनरेगा' का राशि का गौठान में उपयोग कर ग्रामवासी के मूलभूत अधिकार को छीना है।

चलबो गौठान खोलबो पोल कार्यक्रम के तहत बरपाली गौठान में दौरा कर जमीनी हकीकत को देखा गया । बरपाली गौठानो में एक भी गाय मौजूद नहीं थे । गौठान में महिला समूह की बहनों ने बताया कि केंचुआ खाद निर्माण से हम लोगों को ? 50 रोजी पड़ता है वह भी किसानों के खातों से काटकर उनके खाते में ट्रांसफर होता है। गौठान में एक भी गौमाता देखने को नहीं मिला गोबर खरीदी की बात तो सिर्फ कागजों में हो रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिर्रा गौठान को रोल मॉडल प्रस्तुत कर के गए हैं उसकी पोल भी खुल गई। यहां की स्व सहायता समूह की बहनों ने बताया की बरपाली गौठान के दोना पत्तल मशीन को चिर्रा गौठान में ले जाकर रोल मॉडल गौठान प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर 'नरवा, घुरुवा अउ बारी नई कोई चिनाहारी ।

इस कार्यक्रम में कुदमुरा मंडल के कार्यक्रम प्रभारी जिला पंचायत सदस्य संदीप कंवर , जिला महामंत्री टिकेश्वर राठिया, जिला भाजपा के मंत्री श्रीमती रेणुका राठिया, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष उमेश्वर सोनी भाजपा कुदमुरा मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मी श्रीवास, महामंत्री राजू गुप्ता और हेमलाल झारिया, विक्की अग्रवाल शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला सहसंयोजक सुमित वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष समेलाल कंवर,युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष धनंजय चौहान महामंत्री दिनेश प्रजापति, राजेंद्र वस्त्रकार,मीडिया प्रभारी मनजीत सिंह यादव, सुरेंद्र चौहान, दिन्देश चौहान, गेवराज कंवर, रामजीवन कंवर, मोहम्मद हारून खान, बंधु यादव, संतोष, श्रीमती सुकवारा राठिया और बरपाली पंचायत प्रतिनिधि सहित महिला समूह की बहन और आम नागरिक उपस्थित थे।

सिनोधा सरपंच ने गांव के दबंगों के विरुद्ध किया शिकायत

दामोदर चंद्राकर, धनजीवन चंद्राकर तथा द्वारका चंद्राकर गांव में दिखा रहे हैं विधायक के नाम का धौंस

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार भाटापारा थाना जिले में ग्राम पंचायत के कई पंचायतों का बड़ा ही बुरा हाल है क्योंकि आज के दिनांक में पंचायतों पर काम की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण गांव के सरपंच उच्च अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक नाराजगी जाहिर करते रहते हैं मगर कुछ लोगों को काम मिलता है तो वह कराते रहते हैं और जो सरकारी कामकाज होते रहते हैं उनमें भी कई तरह का दखल बाजी गांव के रसूखदार लोगों के द्वारा किया जाता है कुछ ऐसा ही ताजा मामला ग्राम पंचायत सिनोधा विकासखंड कसडोल का है जहां पर बीते दिवस सुबह करीब 8-9 बजे ग्राम पंचायत सिनोधा में जल संसाधन विभाग के द्वारा जेसीबी की गाड़ी आई थी जहां पर पानी टंकी बनना है उसे खोदने हेतु, मगर गांव के ही दबंग लोगों के द्वारा पंचायत इस्तरी कार्य को निजी बात में लेते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच के घर के सामने जाकर गंदी गंदी गालियां देते हुए अपनी गुस्सा जाहिर करते हुए दिखे यहां तक कि कसडोल विधायक शकुंतला साहू का नाम का धौस भी बताते हुए दिखे।

यहां तक भी कह दिया कि जाओ जो करना है कर लो जहां जाना है जाओ मैं विधायक का आदमी हूं मेरा कुछ नहीं हो सकता तुम लोग नीचे जाति के हो और ग्राम पंचायत में मुखिया बन गए हो कुछ जानते भी नहीं हो यह हमारी मालगुजारी जमीन है जहां पर आज खुदाई करवाने के लिए कह रहे हो ऐसा कहते हुए बलपूर्वक घर के सामने जाकर गंदी गंदी गालियां देते हुए अप्शब्दों का प्रयोग किया जिनसे नाराजगी एवं मानसिक प्रताना जैसे महसूस एवं अपमानित शब्दों का उपयोग को देखते हुए ग्राम पंचायत सिनोधा सरपंच श्रीमती सपना मांझी के द्वारा कसडोल थाने पर जाकर शिकायत की गई।

ग्राम पंचायत सिनोधा हमेशा बना रहता है सुर्खियों में

ग्रामपंचायत सिनोधा लगभग जबसे नया पंचवर्षीय चुनाव हुआ है तब से लेकर आज दिनांक तक कुछ न कुछ उथल-पुथल देखने को मिलता रहता है ग्राम पंचायत में मुखिया एवं कुछ और लोगों के खिलाफ गांव के ही लोगों के द्वारा रसूखदारी, दादागिरी, दबंगई दिखाते हुए प्रताड़ित करते रहते हैं और बीते वर्ष में यह भी मालूम पड़ा कि ग्राम पंचायत के सरपंच के पूरे परिवार तथा और भी लोगों के साथ ग्राम पंचायत के निवासियों के द्वारा हुक्का पानी बंद करा दिया गया था जिसको लेकर के भी ग्राम पंचायत सिनोधा सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कसडोल को ज्ञापन सौंपा गया था जिस पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी रहे मिथिलेश डोंडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार, नायब तहसीलदार,मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आर आई, पटवारी, कसडोल पुलिस और संबंधित अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत सिनोधा जाकर जन चौपाल जैसा कार्यक्रम किया और पूरे गांव वालों को तत्काल बुलवाया गया जिस पर पूरे ग्राम वासी उपस्थित रहे तथा सभी के बीच में यह पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली गई तब पता चला कि गांव के ही रसूखदार लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत सिनोधा में बाबा अंबेडकर के बनाए हुए कानून संविधान जैसे नियम भी गांव वालों के द्वारा नियम बनाया गया है जिस पर उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर गांव के ही लोगों के द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाती है की बात पता चला तब अनुविभागीय अधिकारी मिथिलेश डोंडें के द्वारा इन सभी बातों की विरोध की गई और इन सभी बातों को खंडन करके पुनः आम नागरिक और आम जनमानस की तरह एक साथ सब मिलजुल कर रहने एवं नियम को अपने हाथ में ना लेने की बात समझाइश देते हुए कहा गया और पूरे ग्राम वासियों के द्वारा एक पंचनामा रिपोर्ट भी तैयार हुआ जिसमें पूरे गांव वालों के द्वारा यह बात भी कही गई कि किसी भी तरह से कोई भी विवाद या शिकवा शिकायत आवेदन नहीं किया जाएगा गांव में शांतिपूर्ण माहौल रखा जाएगा मगर उसी में से आज भी रसूखदार लोग दामोदर चंद्राकर, धनजीवन चंद्राकर एवं द्वारका चंद्राकर के द्वारा पुनः उस कार्य को अवहेलना करते हुए तथा धौस बताते हुए विधायक का नाम प्रयोग करते हुए पुनः इस तरह से धमकाने चमकाने गाली गलौज ऐसे कारनामे करते हुए दिखे।

जपं मानपुर के साधारण सभा की बैठक में शामिल हुए संसदीय सचिव मंडावी

मानपुर। विधायक ने वाको में 3 लाख रुपए लागत के सामुदायिक भवन निर्माण का किया भूमिपूजन मोहल्ला, विधायक इंद्रशाह मंडावी गुरुवार को मानपुर विकासखंड के दौरे पर रहे जहां उन्होंने सबसे पहले जनपद पंचायत मानपुर में आयोजित साधारण सभा की बैठक में शामिल हुए। साधारण सभा बैठक की शुरुवात में ही झीरम हमले में शहीद हुए जवान एवं नेताओ के याद में श्रद्धांजलि अर्पित किए। साधारण सभा की बैठक में विधायक ने स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यानिकी विभाग, मनरेगा शाखा, आवास शाखा, लोक शिक्षण से संबंधित विभागों के कार्ययोजना, अधूरे कार्य के प्रगति तथा सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों से सवाल जवाब किया। उन्होंने शासन के योजनाएं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु सक्रिय रहने कहा। इस दौरान विभाग प्रमुखों के द्वारा विधायक से मांग भी किया गया जिसका उच्च स्तर पर बात करके त्वरित निराकरण कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष दिनेश शाह मंडावी, उपाध्यक्ष सईदा खान, सभापति अभिमन्यु मंडावी, सुशीला भंडारी, छाया उईके, चाणक्य मेरिया, कल्याण टेकाम, रेणु तांडिया, वेदकुंवर वालको, जानकी पुंगाटी, खेमिका बोगा, तीजन निषाद श्रवण बढ़ाई, दुर्गा मेरिया तथा समस्त विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके बाद विधायक ग्राम कहडबरी में एक दुखद कार्यक्रम में शामिल हुए जहां रोजगार सहायक सराधु भूआर्य का सर्पदंश से आकस्मिक मृत्यु हो गई। विधायक कहडबरी में सीधे शवदाह स्थान पहुंचकर अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद विधायक सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंचे जहां बैठकर शोक संतप्त उनकी धर्मपत्नी व परिवार वालो को ढांढस बंधाया।

इसके बाद विधायक ग्राम पंचायत मांडरी के वाको पहुंचे जहां उन्होंने विधायक निधि 3 लाख रुपए लागत राशि से बनने वाली सामुदायिक भवन का भूमिपूजन किया। तत्पश्चात देवराम तुलावी के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर उनके पुत्र सुरेश तुलावी व पुत्रवधू को आशीर्वाद प्रदान किया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भंडारगांव में भालुओं ने किया बुजुर्ग पर हमला, गंभीर

अंबिकापुर। उदयपुर वन परिक्षेत्र के भंडारगांव पहाड़ी मंदिर के नजदीक दो भालू ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कालेज अस्पताल अंबिकापुर में रिफर किया गया है जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उदयपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम भंडारगांव जंगल पहाड़ी पर स्थित मंदिर की ओर जा रहे सिगन दास (55) को मंदिर से कुछ दूर पहले बरगद पेड़ के पास पहले से मौजूद दो भालुओं ने हमला कर दिया। भालुओं ने बुजुर्ग के सिर,चेहरे और जांघ को कई जगहों पर नोच डाला है। वृद्ध के दाहिने गाल और सिर को बुरी तरह नोच देने से अत्यधिक रक्तस्राव के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जोर-जोर से आवाज लगाना शुरू किया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और भालुओं को खदेड़ा। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को डायल 112 की टीम द्वारा तत्काल सीएचसी उदयपुर उपचार के लिए लाया गया। यहां डा. अनुजा बेक की निगरानी में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज चिकित्सालय रिफर कर दिया गया।

सांप ने की शहर की बत्ती गुल ट्रांसफार्मर में लगे तार पर चलने से हुआ शार्ट सर्किट

जगदलपुर। भीषण गर्मी का दौर नौपता शुरू होने के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक सांप ने आधे शहर की बत्ती गुल कर दी। पढ़ने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन है सही। सांप 11 केवी के मुख्य ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बैठ गया। इसके बाद एक तार से दूसरे पर जाने लगा, तभी शार्ट सर्किट हो गया। इसके चलते शहर आधे हिस्से में लाइट चली गई। हालांकि सूचना मिलने पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सांप को निकालकर सप्लाई बहाल की गई। जानकारी के मुताबिक, जगदलपुर शहर में शुक्रवार को अचानक से कई इलाकों में लाइट चली गई। काफी देर तक लाइट नहीं आई तो ऑनलाइन शिकायतों के साथ ही विभाग के फोन भी बजने लगे। इस पर बिजली विभाग को पता चला कि मुख्य लाइन में फॉल्ट आ गया। उसे ढूंढते हुए कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय के पीछे लगे 11 केवी के हाई वोल्टेज लाइन तक पहुंच गए। जांच के दौरान वहीं से तकनीकी खराबी का पता चला।

यात्री बस पलटी, एक दर्जन से ज्यादा घायल, तीन गंभीर

कोरबा। जेंजरा के पास तेज रफ्तार यात्री बस बाइपास मार्ग से आ रहे ट्रक से टकरा कर अनियंत्रित हो पलट गई। घटना में एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इनमें तीन को गंभीर रूप से चोंट लगी। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने घायलों को बस से बाहर निकाला और डायल 112 की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। छोटे वाहन हो या फिर बड़े वाहनों को तेज गति से चालक चला रहे हैं। इससे दुर्घटनाएं बढते जा रही है। गुरूवार को कटघोरा थाना अंतर्गत तेज रफ्तार बस पलट गई। बताया जा रहा है कि कटघोरा के जेंजरा बाइपास चौराहे पर कोरबा से कटघोरा की ओर आ रही तेज़ रफ़्तार साईं कृपा बस क्रमांक सीजी 11 जी 1109 चौक के पास बाइपास मार्ग से आ रहे ट्रक से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके साथ ही चौराहे पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बस में बैठे यात्रियों के चीख पुकार की आवाज़ आने लगी। इस बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस व डायल 112 को दी।

अस्पताल में नेत्र चिकित्सक नहीं, मरीजों को परेशानी

नगरी। नगरी विकासखंड के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी में वर्षों से नेत्र चिकित्सा अधिकारी की कमी महसूस की जा रही है। मालूम हो कि नगरी क्षेत्र में आज तक एक विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा अधिकारी की स्थापना नहीं हो पाई है। जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम ने बताया कि आज नगरी की आबादी नगर पंचायत मुख्यालय, विकासखंड जनपद का मुख्यालय, अनुभाग अधिकारी कार्यालय का दर्जा मिला, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी की बात की जाती है। ऐसे में क्षेत्र ही है यहां वरिष्ठ जनों के एवं एवं से संबंधित विभिन्न व्याधियों के उपचार के लिए धमतरी रायपुर पर निर्भर रहना होता है। नगरी अस्पताल में एक नेत्र सहायक पदस्थ था उन्हें भी अन्यत्र पदस्थ कर दिया गया है। अस्पताल में नेत्र चिकित्सा अधिकारी की कमी बहुत ही दुर्भाग्य जनक है।दिनेश्वरी नेताम ने स्थानीय जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर अभिलंब नगरी स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु मांग की है।

30 रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस

बिलासपुर। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए ‘अमृत भारत स्टेशन’ योजना नाम से एक नई नीति तैयार की है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 30 रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन के विकास के लिए दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार कर उनका कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायगढ़, बाराद्वार, चाम्पा, नैला, अकलतरा, कोरबा, उसलापुर, पेंड्रारोड, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, भिलाई, बालोद, दल्ली राजहरा, भानुप्रतापपुर, सरोना, मरोदा, मंदिर हसौद, उरकुरा, भिलाई नगर, बिल्हा, निपानिया, भाटापारा, हथबंद, तिल्दा नेवरा, रायपुर, राजनन्दगाँव, डोंगरगढ़ स्टेशन स्टेशन शामिल किये गए हैं । योजना में रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

तोड़ूदस्ता टीम ने फैलाकर रखे समानों को हटवाया, सड़क को कराया मुक्त

कोरबा। निगम प्रशासन का बेजाकब्जा हटाओ तोड़ूदस्ता टीम ने गुरूवार को सुभाष चौक मार्ग में दुकानों के सामने सामान फैलाकर रखने वाले व्यवसाइयों को वापस सामान दुकान के अंदर रखवाया। पुष्पलता उद्यान के सामने सड़क किनारे फुटपाथ पर कब्जा कर दुकान लगाने वाले फल व्यवाइयों के ठेले खोमचे से सड़क को मुक्त कराया गया।

अभियान को मूर्तरूप देने में नगर निगम के तोड़ूदस्ता प्रभार योगेश राठौर के नेतृत्व कार्रवाई करने कर्मचारियों का दल गुरूवार की सुबह घंटाघर पहुंचा। बताना होगा कि शहर में आवागमन सुगम बनाने के लिए निगम प्रशासन ने फुटपाथ का निर्माण कराया है। आम व्यवसाइयों ने इस पर अपना सामान फैला कर कब्जा कर लिया है। सतत कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से आम राहगीरों को फुटपाथ की जगह सड़क पर चलना पड़ रहा हैं। निगम के तोड़ूदस्ता ने पहले दिन बुधवारी मार्ग में पौनी पसारी की जगह सड़क पर सामान फैलाकर रखने वालों से फुटपाथ को खाली कराया। दूसरे दिन महाराणा प्रताप

मार्ग में अतिक्रमण किए गए फुटपाथ को मुक्त कराया।

बेजाकब्जा हटाओ और तोड़ूदस्ता के नोडल अधिकारी योगेश राठौर ने बताया कि सड़क में दुकान नहीं लगाने की चेतावनी दुकानदारों को दी गई और सामानों को दुकान के अंदर रखवाया गया। अधिकारी ने कहा कि फुटपाथ पर आम राहगीरों का अधिकार है। अधिकारी ने बताया इस बार फिर सामान फैलाकर रखने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। गुरूवार को कोसाबाड़ी में संचालित हटरी के सामने दुकान लगाने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। सब्जी लगानें वालों से फुटपाथ को मुक्त कराया गया है। राठौर का कहना है कि आगामी दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी।

निगम प्रशासन ने सुभाष चौक से लेकर घंटाघर के बीच कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन गुमटी ठेलों का ओपन थियेटर में अब भी कब्जा है। स्मृति उद्यान के पीछे चौपाटी बनने के बाद अब भी उसकी उपयोगिता शुरू नहीं हुई है। गेट में ताला भी नसीब नहीं है। दुकान संचालन नहीं होने की वजह से चौपाटी असामाजिक तत्वों का डेरा बन गया है। दुकान संचालन की दिशा में पहल नहीं की गई तो सड़क से हटाए गए ठेलों का फिर सड़कों के किनारे लगना तय है। फुटपाथ पर बेजाकब्जा की समस्या केवल घंटाघर, सुभाष चौक व कोसाबाड़ी चौक तक ही सीमित नहीं है। टीपी नगर और सीतामढ़ी क्षेत्र में भी कार्रवाई की जरूरत है। मामले तोड़ूदस्ता प्रभारी का कहना है कि कार्रवाई के लिए शहर के आठ अलग-अलग स्थानों को चिन्हित किया गया है। इनमें सीतमाढ़ी व टीपी नगर क्षेत्र भी शामिल है। दो तीन बाद चिन्हांकित किए गए अन्य क्षेत्र में शुरूआत की जाएगी।

देश के युवाओं का रूझान कांग्रेस की ओर : डॉ. पलक वर्मा

कोरबा। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी डॉण्पलक वर्मा संगठन मे कसावट लाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कोरबा प्रवास मे आगमन हुआ। जहां बाल्को मे युवा कांग्रेसियों ने सन्नी सिंह के नेतृत्व मे भव्य स्वागत किया गया, तत्क्षण झिरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई,प्रदेश प्रभारी सुश्री वर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मे युवा कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, कैसे कार्य किए जाए, बुत कमेटी मे कितने लोग हो, कैसे संगठन चुनाव मे काम करेगी इस पर अपनी बातें रखी, उन्होंने ने कहा कि कर्नाटक चुनाव से ये रूझान हैं कि देश की युवा अपना भविष्य अब कांग्रेस की ओर देख रही है।

इस अवसर पर राजीव युवा मितान के जिला समन्वयक श्याम नारायण सोनी ने कहा कि युवा कांग्रेस, कांग्रेस की रीढ़ है, और मजबूती के लिए चाहिए कि संगठन के कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ पूरी आत्मविश्वास के साथ कार्य करे और जहां विश्वास और मेहनत का मेल हो तो वहां सफलता निश्चित तौर पर मिलती है, वही पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नितिन चौरसिया ने कहा की युवा कांग्रेस चुनाव मे हमेशा अपनी महती जिम्मेदारी को निभाते आई है और आज भी उसी ताकत के साथ काम कर रही है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश युवा कांग्रस कार्यालय प्रभारी अनीमेष सिंह, जिला ग्रामीण अध्यक्ष विकास सिंह, प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव शहजाद आलम, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एफ डी मानिकपुरि, विकास डालमिया, महेंद्र थावाइत, पूर्व युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिन चौरसिया, प्रदेश प्रवक्ता पिछड़ा वर्ग पंकज सोनी, पुष्पा पात्र, जितेन्द्र साहू,अंजनी साहू,नरेंद्र यादव, दीपक दास एलालिमा जैसवाल महंत, आबिदअख्तर, ताहिर खान,प्रहलाद साहू,द्वारका देवांगन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रवि नारायण सोनी,मोनू ठाकुर जीशान।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

आयकर विभाग के फैसले को चुनौती देने वाली गांधी परिवार की याचिकाएं खारिज

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनमें उन्होंने हथियार सौदागर संजय भंडारी से जुड़े मामले में आयकर विभाग के मूल्यांकन को सामान्य मूल्यांकन की जगह 'सेंट्रल सर्किल' में स्थानांतरित करने के विभाग के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडियन और आम आदमी पार्टी की वे अलग-अलग याचिकाएं भी खारिज कर दीं, जिनमें समान कानूनी मुद्दे उठाए गए थे। गांधी परिवार ने आयकर प्रधान आयुक्त द्वारा आकलन वर्ष 2018-19 के लिए अपने मामलों को 'सेंट्रल सर्किल' में स्थानांतरित करने के संबंध में जारी आदेश को चुनौती दी थी। सेंट्रल सर्किल को कर चोरी की जांच तथा इसकी रोकथाम का काम सौंपा गया है। वह तलाशी के दौरान जांच शाखा द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को अपने कब्जे में ले लेता है।

नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल हुई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा? इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने यह जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गयाकि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है।

सत्येंद्र जैन को मनी लांड्रिंग केस में मिली अंतरिम जमानत

नईदिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे 10 जुलाई तक चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने को कहा। उसने जैन को अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान मीडिया से बात न करने का भी निर्देश दिया। जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और वह रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या से परेशान हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू ने जैन की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में इलाज की जरूरत बताई जाती है तो जांच एजेंसी इसका विरोध नहीं करेगी।

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच पर स्टे नहीं

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक

बनर्जी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरियों घोटाले के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए कहा गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी, जिसमें रिकॉल अर्जी दाखिल करने के लिए उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने मामले को 10 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा बुलाए जाने के कुछ दिनों बाद सोमवार को बनर्जी ने जोर देकर कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की धमकियां उन्हें सार्वजनिक सेवा से नहीं रोक सकतीं। सीबीआई और ईडी पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं में अभिषेक बनर्जी की कथित भूमिका की जांच कर रहे थे।

पासपोर्ट मामले में राहुल को 3 साल के लिए मिली एनओसी

नईदिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और तीन साल के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया। न्यायाधीश ने गांधी के वकील से कहा कि मैं आंशिक रूप से आपके आवेदन की अनुमति दे रहा हूं। 10 साल के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए। बता दें कि राहुल गांधी ने एक सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मांगी थी। गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी हैं जिसमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। शुक्रवार की सुबह अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिस दौरान स्वामी ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया था कि यह किसी भी योग्यता से रहित है और पासपोर्ट केवल एक वर्ष के लिए जारी किया जाना चाहिए और इसे हर साल रिन्यू करना चाहिए।

केंद्रीय गृहमंत्री बोले- भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है 'सेंगोल'

कांग्रेस को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से नफरत क्यों : शाह

नईदिल्ली। देश में नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक बवाल जारी है। विपक्ष इसके उद्घाटन के बहिष्कार की बात कर रहा है। इन सब के बीच नए संसद भवन में राजदंड सेंगोल स्थापित करने पर भी विवाद जारी है। अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है? उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था।

शाह न आगे कहा कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। उन्होंने कहा कि एक पवित्र शैव मठ, थिरुवदुथुराई अधीनम ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधीनम के इतिहास को झूठा बता रही है! उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। नए संसद भवन में स्थापित होने वाला 'राजदंड' अगस्त 1947 में अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में नेहरू को दिया गया था। इसे इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू गैलरी में रखा गया था।

संवैधानिक और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए : राजनाथ

नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर

राजनीतिक बवाल जारी है। 20 विपक्षी दलों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। रक्षामंत्री राजनाथ ने कहा कि हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से बहिष्कार के निर्णय पर फिर से विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। राजनाथ ने आगे कहा कि संसद भवन का उद्घाटन एक एतिहासिक अवसर है जो 21वीं सदी में फिर नहीं आएगा। हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि जिन राजनीतिक दलों ने बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर फिर विचार करें।

सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं सेंगोल, ये बस राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश : कांग्रेस

नई दिल्ली। नए संसद भवन के उद्घाटन में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है सेंगोल, जिसे सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि आजादी के समय पंडित नेहरू को यह सेंगोल सौंपा गया था लेकिन उसके बाद हिंदू परंपरा के प्रतीक इस सेंगोल को म्यूजियम में रख दिया गया। जिसे अब पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने भाजपा ने दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है और इसे लेकर कोई दस्तावेजी सबूत भी उपलब्ध नहीं हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि राजदंड का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों द्वारा तमिलनाडु में अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा यह इस ब्रिगेड की खासियत है, जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथ्यों को उलझाती है। असल सवाल ये है कि नई संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया है। जयराम रमेश यहीं नहीं रुके और उन्होंने लिखा कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कहा था। इसे लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं, वो गलत हैं।

लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है : अखिलेश यादव

लखनऊ। पिछले कुछ दिनों से राजदंड (सेंगोल) चर्चा का विषय बना हुआ है। पक्ष-विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर इसे लेकर हमलावर हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सेंगोल को लेकर शुक्रवार को अलग बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण (एक-हाथ से दूसरे हाथ में जाने) का प्रतीक है...लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। अपने इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने सेंगोल को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा है। उन्होंने यह दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा।

9 साल मोदी सरकार: कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। हालांकि, इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही हैं। कांग्रेस ने तो नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछे है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से एक दस्तावेज भी जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी से 9 सवाल पूछ रही है। हम चाहते हैं कि इन सवालों पर मोदी चुप्पी तोड़ें। कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर बार-बार कहा गया कि पीएम मोदी चुप्पी तोड़िए। देश से जुड़े इन 9 जरूरी सवालों के जवाब दीजिए।

1- अर्थव्यवस्था- ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है? 2- कृषि और किसान- ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई? काले कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई? 3- भ्रष्टाचार/मित्रवाद- ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इसपर जवाब क्यों नहीं देते कि अड़ानी की फर्जी कंपनियों में 20 हजार करोड़ किसके हैं? 4- चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा- ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आँख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वह आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? 5- सामाजिक सद्भाव- ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है? 6- सामाजिक न्याय- ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? वह जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे है? 7- लोकतांत्रिक संस्थाए- ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई? पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया गया? 8- जनकल्याण की

योजनाएं- ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया? गरीब, आदिवासी एवं जरूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला जा रहा है? 9- करोना मिसमेनेजमेंट- ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया? लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया?

भाजपा का पलटवार

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा नरेन्द्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शायद 9 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन वो झूठ का बड़ा पुलिंदा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भाजपा नेता ने कहा कि आप आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना में आप देश के अंदर के संकल्प को कमजोर मत कीजिए, यह बहुत बड़ा अपमान है। उन लाखों सेवा कर्मियों का, डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस चलाने वालों का जिन्होंने कोविड काल में देश को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज भारत, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज 16 हजार करोड़ रुपये का डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। प्रसाद ने कहा कि भारत मोबाइल मैन्यूफेक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्यूफेक्चरर बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा 10 बिलियन डॉलर का है। प्रसाद ने कहा कि चाहे डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल पेमेंट हो, जीएसटी, मोबाइल मैन्यूफेक्चरिंग, सड़कें, एयरपोर्ट, बिजली, किसानों की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, स्टार्टअप इंडिया की बात हो, आज विकास के हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ये सब कांग्रेस को नहीं दिखता है, तो कोई क्या कर सकता है।

खेल
प्रमुख समाचार

सिंधू मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में, श्रीकांत हारे

नईदिल्ली। दो बार की ओलंपिक चैम्पियन पी

वी सिंधू और एच एस प्रणय मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्रमशः महिला और पुरूष एकल सेमीफाइनल में पहुंच गए जबकि किदाम्बी श्रीकांत हारकर बाहर हो गए। छठी वरीयता प्राप्त सिंधू ने निचली रैंकिंग वाली चीन की यि मान झांग को 21.16, 13.21, 22.20 से मात दी। वहीं प्रणय ने जापान के केंता निशिमोतो को 25.23, 18.21, 21.13 से हराया। विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर काबिज सिंधू ने 18वीं रैंकिंग वाली झांग से आल इंग्लैंड ओपन के अंतिम 32 दौर में मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। सिंधू का सामना दुनिया की नौवें नंबर की खिलाड़ी इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का टी से होगा जिसने चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त यि झि वांग को 21.18, 22.20 से मात दी। ग्रेगोरिया ने अप्रैल में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स फाइनल में सिंधू को सीधे गेम में हराया था । उसके खिलाफ हालांकि सिंधू का कैरियर रिकॉर्ड 7.1 का है। दुनिया के नौवे नंबर के खिलाड़ी प्रणय का सामना क्वालीफायर क्रिस्टियन एडिनाटा से होगा। इंडोनेशिया के क्वालीफायर एडिनाटा ने श्रीकांत को 16.21, 21.16, 21.11 से हरा दिया। प्रणय ने 21 वर्ष के एडिनाटा के खिलाफ कभी नहीं खेला है। इंडोनेशिया के इस खिलाड़ी ने पिछले साल ही सीनियर स्तर पर खेलना शुरू किया। सिंधू और ग्रेगोरिया का पहला गेम काफी रोमांचक रहा। सिंधू एक समय 0.5 से पीछे थी लेकिन उसने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 10.10 कर दिया। इसके बाद सिंधू ने बढत बनाकर 21.16 से जीत दर्ज की। दूसरे गेम में झांग ने सिंधू को वापसी का मौका ही नहीं दिया और अंत तक बढत कायम रखकर मुकाबला निर्णायक गेम में खींच दिया। निर्णायक गेम में मुकाबला बराबरी का था और एक समय स्कोर 17.17 था । इसके बाद सिंधू ने 20.17 की बढत बनाई लेकिन झांग ने अगले तीन अंक लेकर स्कोर बराबर कर लिया। सिंधू ने अगले दो अंक लेकर जीत दर्ज की।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान प्रमुख समाचार

सेंसेक्स फिर हुआ 62 हजारी निफ्टी 18,500 के करीब

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार 600 से अधिक अंकों की तेजी के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सेंसेक्स 629 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 178 अंको की गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,499.35 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 629.07 अंक यानी 1.02 फीसदी मजबूत होकर 62,501.69 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,529.83 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 61,911.61 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 178.20 अंक यानी 0.97 फीसदी चढ़ा। निफ्टी दिन के अंत में 18,499.35 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,508.55 की उंचाई तक गया और नीचे में 18,333.15 तक आया।

सेल का नेट प्रॉफिट चौथी तिमाही में 50% से अधिक घटा

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल

ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 50 प्रतिशत से अधिक घटकर 1,159.21 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने बताया कि आय में कमी के चलते उसका शुद्ध लाभ घटा। सेल ने गुरुवार को शेयर बाजारों के बताया कि उसने वित्त वर्ष 2021-22 की समान तिमाही में 2,478.82 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय घटकर 29,416.39 करोड़ रुपये रह गई, जो इससे पिछले साल की समान अवधि में 31,175.25 करोड़ रुपये थी। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में प्रति शेयर 0.50 रुपये की सिफारिश की है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अप्रैल में 15 लाख खाता कम हुए

नईदिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के एक्टिव यूजर्स की संख्या अप्रैल में गिरकर 3.12 करोड़ रह गई। पिछले महीने मार्च में यह संख्या 3.27 करोड़ थी। अप्रैल में लगातार दसवें महीने एनएसई के एक्टिव यूजर्स की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एक नोट में कहा कि अप्रैल में 15 लाख खातों की गिरावट, मार्च के 9 लाख खातों की गिरावट की तुलना में बहुत ज्यादा है। स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव यूजर्स को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसने पिछले वर्ष में कम से कम एक बार ट्रेड किया हो। विशेषज्ञ बताते हैं कि अनिश्चित आर्थिक माहौल, एक साल के रिटर्न में कमी और ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों की कम होती दिलचस्पी के कारण एक्टिव यूजर्स की संख्या में गिरावट आ रही है। पिछले नौ-दस महीनों में, भारतीय शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

पेज इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट चौथी तिमाही में 58.8% घटा

नईदिल्ली। परिधान विनिर्माता पेज

इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शुद्ध लाभ मार्च 2023 में खत्म हुई तिमाही के दौरान 58.87 फीसदी घटकर 78.35 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजार को बताया कि इससे एक साल पहले जनवरी-मार्च 2022 के दौरान उसने 190.52 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीआईएल) की परिचालन आय 12.78 फीसदी घटकर 969.09 करोड़ रुपये रह गई। कंपनी का कुल खर्च वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 869.68 करोड़ रुपये था, जबकि यह आंकड़ा एक साल पहले इसी अवधि में 870.04 करोड़ रुपये था।

मोदी सरकार के बेहतरीन नौ साल, अर्थव्यवस्था की तेज हुई चाल

अश्विनी महाजन

जब भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाली एनडीए सरकार ने 26 मई, 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता संभाली, तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद 20 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर था, जो अब 37.3 खरब डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय जो 2014 में 1,573.9 डॉलर थी, अब 2023 में 2,601 डॉलर है। रुपयों में मौजूदा कीमतों पर यह जीडीपी 2013-14 में 104.73 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 272.04 लाख करोड़ रुपये हो गई है। जीडीपी के मामले में भारत 2014 में 10वें स्थान पर था और अब यह पांचवें स्थान पर है।

माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कुशल- क्षेम की कोई गारंटी नहीं है। पिछले कुछ समय से देश में आय की असमानताओं में भी भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 की कोरोना महामारी ने हालांकि सभी वर्गों को प्रभावित किया, पर उसकी सबसे ज्यादा मार मजदूरों एवं अन्य कामगारों और व्यवसायियों, खासतौर पर छोटे व्यवसायियों पर पड़ी, जिसके कारण उनकी आमदनी और कुशल-क्षेम, दोनों प्रभावित हुए। 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त अनाज, इलाज और संपूर्ण जनसंख्या को कोविड निरोधी टीका लगाने में भारत दुनिया के मुल्कों में अग्रणी रहा। ग्रामीण बेरोजगारों के लिए पहले से चल रही 'मनरेगा' योजना पर पिछले नौ सालों में लगभग 5.89 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जुलाई 2008 और जून 2009 के बीच किए गए एनएसएसओ सर्वेक्षण के 65वें दौर के अनुसार, देश में 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवार और 2.1 प्रतिशत शहरी परिवार कच्चे घरों में रहते थे, जो 3.15 करोड़ परिवारों के बराबर था। 2015 के बाद पक्के

घरों के निर्माण में बड़ी प्रगति हुई है, जहां पीएम आवास योजना- ग्रामीण और शहरी के तहत सरकारी सहायता से मकान बनाने के लिए 4.1 करोड़ परिवारों (ग्रामीण क्षेत्रों में 2.85 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.23 करोड़) को सहायता दी गई है; और आठ साल से भी कम समय में अब तक 2.87 करोड़ घर बनाए गए हैं। इसे ग्रामीण व शहरी गरीबों के जीवन स्तर को उठाने का बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

वर्ष 2014-15 के दौरान 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण हो रहा था, जो 2022-23 में बढ़कर 22.23 किमी प्रतिदिन हो गया है। जब हम यूपीए सरकार से तुलना करते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण पर सालाना 10,000 करोड़ रुपये खर्च होता था, जो एनडीए के दौरान बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये हो गया है। सड़कों के अलावा जलमार्ग, रेलवे का विस्तार और वंदे भारत के नाम से स्वदेशी तीव्र गाड़ियों का विस्तार हुआ है। 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, जो अब दोगुने यानी 148 हो गए हैं।

मोदी सरकार के नौ साल भारतीय अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए बेहतरीन माने जा सकते हैं। सदी की सबसे खराब महामारी के बावजूद इन नौ वर्षों में, भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है, न केवल जीडीपी में रैंकिंग के मामले में, बल्कि अमीर और गरीब देशों के साथ सहयोग के मामले में भी। कोरोना काल में जब अमीर देश खुदगर्ज बनते जा रहे थे, तब भारत ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए कई देशों को दवा और वैक्सीन उपलब्ध कराई। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, रूस से तेल न खरीदने के भारी दबाव के बावजूद भारत मजबूती से खड़ा रहा। मोदी सरकार की यात्रा बहुत सहज नहीं थी, क्योंकि इसे भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन, कृषि कानूनों को लागू करने, विमुद्रीकरण, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) यानी पड़ोसी देशों के सताए गए गैर-मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त करने के अपने फैसले के विरोध का सामना करना पड़ा था। मोदी सरकार के फैसलों के विरोध के बावजूद कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी दुर्भावना को साबित नहीं कर सका। इन फैसलों को लेते समय मोदी सरकार ने विपक्ष के प्रति भी अपनी पूरी संवेदनशीलता दिखाई, और मीडिया के कोप का सामना करते हुए भी सुधार करने के लिए सरकार तैयार दिखाई दी।

ज्ञान, शक्ति और कर्म का संगम है संसद भवन

प्रणय कुमार

संसद का शाब्दिक अर्थ है, जहां सभी बराबर होकर बैठते हैं। सम+ सद् = संसद। सम् का मतलब बराबर और सद् का मतलब बैठना, आसीन होना या वास करना। संसद एक समूहवाची शब्द है, जिसके मूल में साथ बैठने का भाव निहित है। समूह की उपस्थिति बहुधा रचनात्मक उद्देश्य के लिए होती है। इसीलिए हमारे यहां पार्लियामेन्ट को परिभाषित करना हुआ तो संसद शब्द को चुना गया। दुनिया की अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सर्वोच्च सभा के लिए जो नाम मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं - सीनेट (अमेरिका), पार्लियामेंट (ब्रिटेन), ड्यूमा (रूस)। उसी तरह भारतीय जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्च सभा के लिए संसद नाम रखा गया।

भारत लोकतंत्र की जननी है। इसलिए भारत के प्राचीन गणराज्यों में इससे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग भी श्रुति, स्मृति, पुराण, महाकाव्य आदि ग्रंथों में मिलता है। विश, जन, प्रजा, गण, कुल, ग्राम, जनपद, सभा, समिति, परिषद, संघ, निकाय जैसे अनेक शब्दों एवं संस्थाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिनसे पुष्टि होती है कि उस समय भी भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व था। वैदिक वाङ्मय पर दृष्टि डालने से दो प्रकार की गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएँ सामने आती हैं। एक जिसमें राजा निर्वाचित किया जाता था और दूसरा जिसमें राज्य की शक्ति सभा या परिषद में निहित होती थी। इसे राजाधीन एवं गणाधीन शासन-तंत्र कहा जा सकता है।

वैदिक राजा का निर्वाचन समिति में एकत्रित होने वाले लोगों द्वारा किया जाता था। समिति सार्वजनिक कार्यों को संपादित करने वाली संस्थाओं में सर्वप्रमुख थी। यह जनसामान्य का प्रतिनिधित्व करती थी। परिचर्चा और पारस्परिक सम्मति से निर्णय लिए जाते थे। वहीं सभा समिति के अधीन कार्य करती थी। इसमें वृद्ध एवं अनुभवी लोगों का विशेष स्थान प्राप्त होता था। यह चयनित लोगों की

स्थायी संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित राज्याभिषेक के आरंभ से अंत तक के कार्यव्यवहार से स्पष्ट होता है कि राजा को राजपद प्राप्त करने से पूर्व राष्ट्र के विभिन्न अंगों की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी। वह राष्ट्र के भिन्न-भिन्न स्थानों की मिट्टी, जल, वर्ण, वायु, पर्वत और संपूर्ण प्रजा का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए उसके राज्याभिषेक में सबको सम्मिलित किया जाता था। उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श, स्वीकृति और प्रजा के कल्याण की भावना से कार्य संपादित करना होता था। यहां तक कि उसके पुनर्निर्वाचन की भी निश्चित प्रक्रिया और व्यवस्था थी। उल्लेखनीय है कि समिति और सभा की सदस्यता जन्म के बजाय कर्म पर आधारित थी। नीति, सैन्य एवं सार्वजनिक हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श एवं नियमन हेतु विदथ-सभा का भी उल्लेख मिलता है, जिसका प्रयोग ऋग्वेद में सौ से अधिक बार किया गया है। कहने का आशय यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था यह भारतीय मानस में निहित है। हम स्वभाव से लोकतांत्रिक है इसलिए बीते 75 सालों में कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो भारत में लोकतंत्र उत्तरोत्तर प्रबल और परिस्कृत हुआ है। लेकिन इस लोकतंत्र के मुख्य केन्द्र संसद का काम काज एक ऐसे भवन से चल रहा था जो ब्रिटिश काल में निर्मित किया गया था। हालांकि यह भारत के ही 64 योगिनी मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित बताया जाता है लेकिन बीतते समय के साथ यह न सिर्फ कमजोर होने लगा था बल्कि बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में भी अक्षम हो चला था। ऐसे में स्वतंत्र भारत के अमृतकाल में नयी संसद भवन का निर्माण निश्चित रूप से भारतीय लोक मानस के लिए गौरव की बात है।

आजादी के अमृत-काल की स्वर्णिम बेला में, आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी देश को नए संसद-भवन की सौगात देने जा रहे हैं। यह लगभग 28 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। 10 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद-भवन का शिलान्यास किया था। लोकतंत्र के इस महान मंदिर को भव्य, अद्भुत एवं अलौकिक स्वरूप में देखना भला किस भारतीय को सुंदर व सुखद नहीं लगेगा! नए संसद-भवन की छतों और दीवारों पर देश की कला एवं संस्कृति के विविध रंग उकेरे गए हैं। यह विविधता में एकता की सही स्वरूप में प्रतिबिंबित करते हैं। 200 से भी अधिक कलाकर्मी एवं शिल्पकार इससे सीधे तौर पर जुड़े रहे। दिल्ली भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है, इसलिए इसमें भूकंपरोधी तकनीक के इस्तेमाल के साथ-साथ सुरक्षा के सभी सर्वोच्च मानकों का भी ध्यान रखा गया है। इस नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 384 से अधिक सीटें हैं। इसमें दोनों सदनों के साझा सत्र में 1272 सांसदों से भी अधिक के बैठने की व्यवस्था है। दर्शक दीर्घा एवं गणमान्य अतिथियों के बैठने के लिए भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। दर्शक दीर्घा गैलरी में 336 लोगों के बैठने का प्रबंध किया गया है। नए संसद भवन को त्रिकोण के आकार में डिजाइन किया गया है। इसे मौजूदा परिसर के पास ही बनाया गया है। 64,500 वर्गमीटर में बनने वाले इस नए संसद-भवन की लागत पहले लगभग 971 करोड़ रुपए आंकी गई थी, परंतु लोकार्पण तक इसकी कीमत 1250 करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है। इसे चार मंजिला रखा गया है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री एवं सांसदों के आने-जाने हेतु सुगमता की दृष्टि से तीन मुख्य प्रवेश-द्वार हैं। इनके नाम - ज्ञान-द्वार, शक्ति-द्वार एवं कर्म-द्वार रखे गए हैं। इसे पेपरलेस और प्रदूषणमुक्त रखे जाने का प्रयास किया गया है। इसमें बिजली की 30 प्रतिशत कम खपत होगी। नए संसद-भवन में हर सांसद के लिए उनका एक कार्यालय भी होगी। विदित हो कि मौजूदा संसद-भवन का निर्माण ब्रिटिश भारत में एड्विन लैंडसियर लूट्यन्स और सर हर्बर्ट बेकर ने किया था। इसे 1921 में प्रारंभ कर 1927 में पूरा किया गया था। नए संसद-भवन के निर्माण के पश्चात मौजूदा भवन को पुरातात्विक धरोहर एवं संग्रहालय के रूप में संजोए-सहेजे जाने की योजना है। वहीं नए संसद-भवन के निर्माण में भारत के वास्तुकार, भारत का धन और भारत का श्रम लगा है। इसके वास्तुकार (आर्किटेक्ट) बिमल पटेल हैं, जो इस समय के मशहूर एवं जाने-माने आर्किटेक्ट हैं। इसके निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 2000 इंजीनियर एवं कामगार तथा परोक्ष रूप से लगभग 9000 कामगार संबद्ध एवं सक्रिय रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नया संसद-भवन भारत की शताब्दियों पुरानी लोकतांत्रिक यात्रा का गौरवशाली कीर्तिस्तंभ है। नि:संदेह यह देश की लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। वह नूतन और पुरातन के सह-अस्तित्व का उदाहरण बनकर देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। परंतु यहाँ यह भी स्मरण रहे कि इस भवन की वास्तविक प्रतिष्ठा इसकी ऊंचाई, भव्यता या विशालता से नहीं, अपितु इसमें चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के आचार, विचार एवं व्यवहार से सुनिश्चित होगी। इसकी महत्ता एवं सार्थकता इसके आकार-प्रकार से कहीं अधिक जन-मन की आशाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति पर निर्भर करेगी।

संसद भवन के उद्घाटन की लड़ाई गठबंधन तक आई

संतोष पाठक

संसद के नए भवन के उद्घाटन की लड़ाई आखिरकार एनडीए बनाम यूपीए गठबंधन तक पहुंच ही गई है। इसी के साथ यह भी साफ हो गया है कि विपक्षी दलों ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन नहीं करने का मुद्दा उठाकर इसके बहिष्कार का फैसला किया है। दरअसल, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी के विरोध में सभी विपक्षी दलों का एक साझा मोर्चा बनाने के लिए देश भर में राजनीतिक यात्रा करने वाले नेताओं और इन यात्राओं के पीछे मौजूद राजनीतिक दिमाग यह भांप गए कि इस मुद्दे के सहारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया जा सकता है। वर्तमान में पूर्ण और शानदार बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार है। वहीं कर्नाटक में जीत हासिल करने के बाद उत्साह और उमंग से भरी हुई कांग्रेस के नेतृत्व में भी यूपीए गठबंधन चल ही रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज के दौर में यूपीए ही नहीं एनडीए भी कमजोर ही नजर आ रहा है। अकाली दल और उद्धव ठाकरे के अलग हो जाने के बाद अब एनडीए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ताकत पर ही टिका हुआ है तो वहीं सत्ता से बाहर होने की वजह से कांग्रेस के इकबाल में भी कमी आई है। लेकिन संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार के बहाने ही सही कांग्रेस न केवल यूपीए गठबंधन को मजबूत करने में कामयाब होती नजर आ रही है बल्कि अपने साथ कुछ ऐसे दलों को भी जोड़ती नजर आ रही है जो पिछले कुछ सालों से लगातार कांग्रेस का विरोध ही करते नजर आ रहे हैं। देश के जिन 19 विपक्षी राजनीतिक दलों ने साझा बयान जारी कर संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है, उसमें यूपीए गठबंधन में पहले से ही शामिल डीएमके, जेएमएम, एनसीपी और आरजेडी तो शामिल हैं ही। इसके अलावा मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने वाले लेफ्ट फ्रंट के साथ ही कांग्रेस के कट्टर विरोधी आप और टीएमसी जैसे दल भी शामिल हैं। इसमें सपा जैसे राजनीतिक दल भी शामिल हैं जो अपने सबसे मजबूत गढ़ यूपी में कांग्रेस के लिए कोई स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के लिए सबसे खास बात यह भी है कि इन 19 राजनीतिक दलों के साझा बयान में कांग्रेस पार्टी का नाम सबसे ऊपर है। कांग्रेस को अब यह लगने लगा है कि मोदी विरोधी सारे दल उसके झंडे तले उसके साथ आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बनने वाले नए मोर्चे का नाम भले ही कुछ भी हो लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन मजबूत होगा ही। यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस यूपीए वाली राजनीति की काट के लिए ही भाजपा ने एनडीए वाला दांव चल दिया है। बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल भाजपा समेत 14 दलों ने विपक्ष के 19 दलों के बहिष्कार के फैसले की घोर निंदा की और कहा कि यह महज अपमानजनक फैसला नहीं है बल्कि इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। भाजपा, शिंदे वाली शिवसेना, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, एमएनएफ, जेजेपी, रालोजपा, अपना दल (सोनेलाल), आरपीआई (ए), तमिल मनीला कांग्रेस, एआईएडीएमके, आईएमकेएमके और एजेएसयू ने एनडीए की तरफ से साझा बयान जारी कर विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी एकता, राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टि नहीं, बल्कि वोट बैंक की राजनीति के लिए साझा अभ्यास है और भ्रष्टाचार के प्रति स्पष्ट रुझान व झुकाव है। ऐसी पार्टियां कभी भी भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती हैं।

कृपया इनसे सीखें

बुझाई गाँव की प्यास

जब इरादे मजबूत हो तो कामयाबी मिलना तय है, इसका उदाहरण पेश किया है मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक आदिवासी दंपति ने इस दंपति ने कोरोना काल में पानी की समस्या से निजात पाने का संकल्प लिया। फिर क्या था दोनों जुट गए कुआँ खोदने में, महज 20 दिन में उनकी मेहनत रंग लाई और कुआँ खोद डाला व उस कुएँ में पानी भी आ गया है। सतना जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है मझगवाँ विकास खंड की पिण्ड्रा पंचायत का बरहा मवान गाँव। इस गाँव की आबादी लगभग सात सौ है। यहाँ के छोटू मवासी और उसकी पत्नी राजलली ने कोरोना के लॉक डाउन के कारण फुरसत के पलों का उपयोग करने की ठानी। कुआँ खोदकर इस दंपति ने आत्म निर्भरता की मिसाल पेश की है। छोटू बताते हैं कि कोरोना के कारण लॉकडाउन है। हम दोनों पति-पत्नी ने एक दिन सोचा क्यों न कुआँ ही खोद लिया जाए। पानी की समस्या है, एक तो कुआँ खुद जाएगा और दूसरा पानी की समस्या के निराकरण के साथ समय का भी सदुपयोग हो जाएगा। फिर क्या था, दोनों जुट गए कुआँ खोदने में। बीस दिन तक लगातार दोनों मिलकर खोदने में लगे रहे और कुआँ खुद गया। पानी भी आ गया है। अब सरकार से अपेक्षा है कि वह इस कुएँ को पक्का करा दे तो गाँव के लोगों को पीने का पानी मिलने लगेगा। एक तरफ जहाँ आदिवासी दंपत्ति ने कुआँ खोदा है वहीं लोगों को हरी सब्जी उपलब्ध कराने का भी अभियान चलाया है। किचिन गार्डन में सब्जी उगा रहे हैं। राजलली बताती है कि उसने पति के साथ मिलकर कुआँ खोद लिया है तो उसने किचन गार्डन भी लगाया। उसके मन में एक बात है कि जब कुआँ खोदा जा सकता है तो सब कुछ किया जा सकता है। आदिवासी दंपत्ति ने 15 फुट गहरा और पाँच फुट चौड़ा कुआँ खोदा है। इस कुएँ में पानी भी निकल आया है।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1981 सोवियत संघ ने पूर्वी कजाख क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया।
1983 अमेरिका के टेनेसी के बेंटन शहर के पास एक अवैध पटाखे की फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में ग्यारह लोगों की मौत हो गई और कई मील के दायरे में नुकसान हुआ।
1986 यूरोपीय समुदाय ने यूरोपीय ध्वज को अपनाया। यूरोप के ध्वज में एज्योर पृष्ठभूमि पर 12 सुनहरे (पीले) सितारों का एक चक्र होता है। यह यूरोप परिषद और यूरोपीय संघ का ध्वज और प्रतीक है।
1994 नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता रूसी लेखक एलेक्जेंडर सोल्केनित्सिन पश्चिम में 20 वर्ष का निर्वासन समाप्त कर स्वदेश लौटे।
1995 अमेरिकी अभिनेता क्रिस्टोफर रीव को उनके घोड़े से फेंक दिया गया, जिससे उन्हें एक चतुर्भुज बनाया गया; वह बाद में रीढ़ की हड्डी में चोट के साथ लोगों की ओर से एक कार्यकर्ता बन गया।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

अक्ष्युपनिषद् (भाग-6)

गतांक से आगे...

हृदय ग्रन्थियों के उद्घाटित होने पर संशय मिट जाते हैं। जीवन्मुक्त होकर उसकी भावशून्यता की सी स्थिति रहती है। निर्वाण को उपलब्ध न किये जाने पर भी उसकी स्थिति निर्वाण पद को प्राप्त साधक जैसी हो जाती है। उस समय वह निश्चेष्ट दीपक की तरह निश्चल रहता है। छठी भूमिका के पश्चात् वह सातवीं भूमिका की स्थिति प्राप्त करता है.. विदेह-मुक्त की स्थिति ही सातवीं भूमिका कही गयी है। यह भूमिका परम शान्त की है तथा वाणी की सामर्थ्य से अवर्णनीय है।

यह सब भूमिकाओं की सीमारूप है तथा यहाँ सम्पूर्ण योग भूमिकाओं की समाप्ति है। लोकाचार, देहाचार और शास्त्रानुगमन को छोड़कर अपने अध्यास को नष्ट करे। विश्व, प्राज्ञ और तैजस के रूप में यह समस्त विश्व कार स्वरूप ही है। वाच्य और वाचक में अभेदता रहती है और भेद होने पर इसकी उपलब्धि सम्भव नहीं। इन्हें क्रमशः इस प्रकार जाने प्रणव की प्रथम मात्रा अकार विश्व, उकार तैजस और मकार प्राज्ञ रूप है। समाधिकाल से पहले विशेष प्रयासपूर्वक इस सम्बन्ध में चिन्तन-मनन करके स्थूल और सूक्ष्म से क्रमशः सब कुछ चिदात्मा में विलीन करे। चिदात्मा का स्व-स्वरूप स्वीकार करते हुए ऐसा दृढ़ विश्वास करे मैं ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्तारूप, अद्वितीय, परमआनन्द सन्दोह रूप एवं वासुदेव प्रणव कार हूँ। चूँकि आदि, मध्य और अन्त में यह सम्पूर्ण प्रपञ्च दुःख देने वाला ही है, इसलिए हे निष्पाप! सबका परित्याग करके तत्त्वनिष्ठ बने। मैं अज्ञानरूपी अन्धकार से अतीत, सभी प्रकार के आभास से रहित, आनन्दरूप, मलरहित, शुद्ध, मन और वाणी से अगोचर, प्रज्ञानघन, आनन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना करे। यही उपनिषद् (रहस्यमयी विद्या) है।

पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी

पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई, 1894, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, भारत में हुआ था। इनके पिता श्री पुन्नालाल बख्शी खैरागढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी चंद्रकांता संतति उपन्यास के प्रति विशेष आसक्ति के कारण स्कूल से भाग खड़े हुए तथा हेडमास्टर पंडित रविशंकर शुक्ल (मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री) द्वारा जमकर बेतों से पीटे गये। 14वीं शताब्दी में बख्शी जी के पूर्वज श्री लक्ष्मीनिधि राजा के साथ मण्डला से खैरागढ़ में आये थे और तब से यहीं बस गये। बख्शी जी के पूर्वज फतेह सिंह और उनके पुत्र श्रीमान राजा उमराव सिंह दोनों के शासनकाल में श्री उमराव बख्शी राजकवि थे।

पदुमलाल बख्शी की प्राइमरी की शिक्षा खैरागढ़ में ही हुई। 1911 में यह मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में बैठे। हेडमास्टर एन.ए. गुलामअली के निर्देशन पर उनके नाम के साथ उनके पिता का नाम पुन्नालाल लिखा गया। तब से यह अपना पूरा नाम पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी लिखने लगे। 1911 में जबलपुर से निकलने वाली 'हितकारिणी' में बख्शी की प्रथम कहानी 'तारिणी' प्रकाशित हो चुकी थी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने राजनांदगाँव के स्टेट हाई स्कूल में सर्वप्रथम 1916 से 1919 तक संस्कृत शिक्षक के रूप में सेवा की। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने साहित्यिक जीवन का शुभारम्भ कवि के रूप में किया था।

1916 ई. से लेकर लगभग 1925 ई. तक इनकी स्वच्छन्दतावादी प्रकृति की फुटकर कविताएँ तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। बाद में शतदल नाम से इनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को वास्तविक ख्याति आलोचक तथा निबन्धकार के रूप में मिली। सन् 1920 में यह सरस्वती के सहायक संपादक के रूप में नियुक्त किये गये और एक वर्ष के भीतर ही 1921 में वे

सरस्वती के प्रधान संपादक बनाये गये जहाँ वे अपने स्वेच्छा से त्यागपत्र देने (1925) तक उस पद पर बने रहे। सन् 1929 से 1949 तक खैरागढ़ विक्टोरिया हाई स्कूल में अंग्रेज़ी शिक्षक के रूप में नियुक्त रहे। कांकेर में भी कुछ समय तक उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया। तब 'सरस्वती' हिन्दी की एक मात्र ऐसी पत्रिका थी जो हिन्दी साहित्य की आमुख पत्रिका थी।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपादन में प्रारंभ इस पत्रिका के संबंध में सभी विज्ञ पाठक जानते हैं। सन् 1920 में द्विवेदी जी ने पदुमलाल पन्नालाल बख्शी की संपादन क्षमता को नया आयाम देते हुए इन्हें 'सरस्वती' का सहा. संपादक नियुक्त किया। फिर 1921 में वे 'सरस्वती' के प्रधान संपादक बने, यही वो समय था जब विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हिन्दी के स्तरीय साहित्य को संकलित कर 'सरस्वती' का प्रकाशन प्रारंभ रखा। साहित्य जगत् में साहित्यवाचस्पति पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का प्रवेश सर्वप्रथम कवि के रूप में हुआ था। कहा जाता है कवि का व्यक्तित्व जितना सर्वोपरि होगा साहित्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण भी। बख्शी जी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनकी रचनाओं में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट परिलक्षित होता है। बख्शी जी मनसा, वाचा, और कर्मणा से विशुद्ध साहित्यकार थे। मान प्रतिष्ठा पद या कीर्ति की लालसा से कोसों दूर निष्काम कर्मयोगी की भाँति पूरी ईमानदारी और पवित्रता से निश्छल भावों की अभिव्यक्ति को साकार रूप देने की कोशिश में निरन्तर साहित्य सृजन करते रहे। उपन्यास के प्रेमी पाठक होने पर भी अपने को असफल कहते। लेकिन इनके उपन्यासों को पढ़ कर कोई यह नहीं कह सकता कि बख्शी जी असफल उपन्यासकार हैं। आरम्भ में बख्शी जी की दो आलोचनात्मक कृतियाँ प्रकाशित हुईं- हिन्दी साहित्य विमर्श (1924 ई.) और विश्व साहित्य (1924 ई.)।

पापुआ न्यू गिनी क्यों गये प्रधानमंत्री मोदी?

सिद्धार्थ शंकर गौतम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। आमतौर पर पापुआ न्यू गिनी में सूरज ढलने के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता किन्तु भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार किसी का यहां आना सभी अपवादों से परे रहा। यही नहीं, नरेन्द्र मोदी के समकक्ष प्रधानमंत्री जेम्स मारापे हवाई अड्डे पर उनके सम्मान में पैर छूते हुए नजर आये। भारत में इस तस्वीर की खूब चर्चा हुई, लेकिन इस बात पर कोई खास चर्चा नहीं हुई कि प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा क्यों की? पापुआ न्यू गिनी न केवल प्राकृतिक संसाधन के रूप में बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण एक देश है। पापुआ न्यू गिनी मुख्य रूप से वनवासी लोगों का देश है और विविधताओं से भरा हुआ है। लेकिन उसके प्राकृतिक संसाधन और प्रशांत महासागर में उसकी भौगोलिक स्थिति उसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश बना देते हैं।

2014 में नरेन्द्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान भारत और प्रशांत द्वीप समूह सहयोग का गठन किया गया था। यह 1971 में स्थापित प्रशांत द्वीप समूह फोरम की तर्ज पर गठित किया गया ताकि अपने संसाधन संपन्न विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के साथ भारत और ये द्वीप समूह तरलीकृत प्राकृतिक गैस तथा हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को साझा कर नए बाजार का विकल्प तैयार कर सके। इस संगठन के गठन का एक उद्देश्य प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को सामरिक रूप से काउण्टर करना भी था। भारत की इस कूटनीति को अमेरिका

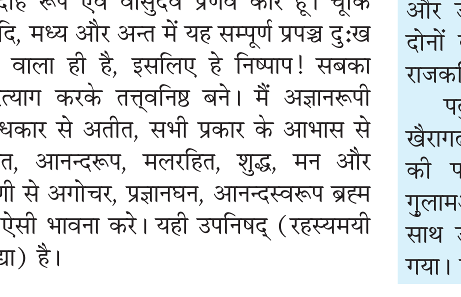

का भी साथ मिल रहा है क्योंकि चीन का प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव उसके परमाणु तथा सामरिक हितों को कमजोर करेगा।

हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के एक प्रमुख कारणों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साय संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, जर्मनी-जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता थे। किन्तु वृहद् नजरिये से देखें तो प्रशांत महासागर में स्थित ये द्वीप समूह भी शाही जापान और इंग्लैंड के बीच युद्ध का प्रबल कारण बना। चूंकि उस कालखंड में जापान का इन द्वीप समूहों पर बड़ा प्रभाव था और इंग्लैंड अपने उपनिवेश का इस क्षेत्र में विस्तार करने में जुटा था, जिस कारण दोनों देशों में तल्खी बढ़ी। विश्व युद्ध के अंतिम चरण में मित्र राष्ट्र अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैन्य अड्डे पर जापानी आक्रमण के बाद सारे समीकरण बदल गए। अमेरिका ने परमाणु हमला कर जापान को झुका दिया और इंग्लैंड भी बदलती वैश्विक परिस्थिति के कारण उसकी ताकत के समक्ष नतमस्तक हो गया। कमजोर होता इंग्लैंड अमेरिका के लिए प्रशांत महासागर क्षेत्र को खाली छोड़ गया। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने अनेक सैन्य अड्डे स्थापित किए और एक मजबूत ब्लू वाटर नेवी का गठन किया जिसका तात्पर्य है अपनी समुद्री सीमाओं की तुलना में बहुत बड़े समुद्री क्षेत्र में खुद को स्थापित करने की क्षमता रखना। हालांकि 1960 के बाद मजबूत होते चीन ने धीरे-धीरे अमेरिका की इस क्षेत्र में बादशाहत को चुनौती दी और चीन सैन्य अभ्यास के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग करने लगा। यही बात अमेरिका को कचोटती है और यही कारण है कि उसने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिजी, वियतनाम और ब्रूनेई के साथ इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का गठन किया। इसका उद्देश्य था व्यापार के माध्यम से इन देशों को एक छत के नीचे लाकर इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देना। चूँकि चीन इस क्षेत्र को अपने बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा मानता है और बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश करता है अतः इसकी काट के रूप में जी-7 समूह ने इन द्वीप समूह के देशों में विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिये 600 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। ऐसा करके अमेरिका और उसके सहयोगी देश प्रशांत महासागर में स्थित देशों का चीन के प्रति झुकाव कम करना चाहते हैं। यदि अमेरिका महाशक्ति बने रहना चाहता है तो उसे प्रशांत महासागर क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी होगी। इसके लिए वह भारत को अपने साथी के रूप में देख रहा है। उधर चीन की विस्तारवादी नीति और भारत विरोध को कमजोर करने के लिए ऐसा करना भारत के लिए भी आवश्यक है। यही कारण है कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन देशों में भारत की आर्थिक, सामरिक व वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया और %भारत और प्रशांत द्वीप समूह सहयोग% का गठन कर इस क्षेत्र में मजबूती से अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। फिजी और पापुआ न्यू गिनी में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है अतः इन देशों से व्यापार संबंध पहले के मुकाबले और सुदृढ़ हुए हैं। साथ ही कुक आइलैंड्स, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नौरू, नीयू, पलाऊ, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वानुआतु के साथ भी अब संबंधों को नए आयाम दिए जा रहे हैं। इन देशों के साथ डिजिटल स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु, भू-सामरिक परिप्रेक्ष्य और आपदा के जोखिम को कम करने जैसे मुद्दों पर साझेदारी की जा रही है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर भी दोनों पक्ष आम राय बना रहे हैं। भारत ने दुनिया की भविष्यगत स्थिति को भांपते हुए इन देशों को अनुदान के तौर पर 2,00,000 अमेरिकी डॉलर सालाना सहायता करने का वादा किया है।

इसके अलावा इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में लोकतंत्र अभी मजबूत नहीं है। ऐसे में चीन का हस्तक्षेप इनके आतंरिक व राजनीतिक मामलों में होता है। भारत का इन देशों के निकट आना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति को भी कुंद करेगा। इन देशों का भारत के साथ आना इनके लिए भी विकास के द्वार खोलेगा क्योंकि चीन ने अपने कर्ज के जाल में इनकी अर्थव्यवस्था को चौपट करते हुए इनके संसाधनों का दोहन किया है। मोदी की पापुआ न्यू गिनी यात्रा से निश्चय ही प्रशांत महासागर पॉलिसी को नया बल मिला है। जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति ने पैर छूकर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया है उससे इस बात का संकेत भी मिलता है प्रशांत महासागर के द्वीप समूह चीन की अपेक्षा भारत के साथ अधिक सहज और आत्मीय हैं।

बापू की दिनचर्या

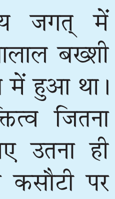

रोगी-सेवा और चिकित्सा (भाग-7)

गतांक से आगे...

बापू के उपचार और उनकी स्नेहपूर्ण देखभाल से वे पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाए थे। अंत में उनको %कुष्ठधाम% भेजना पड़ा। उन्होंने कहा था कि जितने प्रेम से मुझ अस्पृश्य महारोगी को बापू ने अपनाया और अपने हाथों से मेरी सेवा की, उतनी सेवा मेरी माँ भी नहीं करती। बापू के प्रेम से ही अभी तक मैं जिंदा हूँ। एक बार वर्धा में कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक के बीच बापू शास्त्रीजी की परिचर्या संबंधी हिदायत देने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय संभवत: कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे बापू पर बिगड़ पड़े। झल्लाकर उन्होंने कहा कि क्या स्वराज्य और कार्यसमिति से बढ़ कर जरूरी काम है? बापू दृढ़ता के स्वर में बोले- है, मेरे लिए यह स्वराज्य से बढ़कर हैं! एक प्रसंग सन् 1939 का है। बापू वाइसराय से बातें करने शिमला गए। वार्ताएं पाँच-सात दिन के लिए स्थगित हुई तो बापू परचुरे शास्त्री की सेवा-परिचर्या के लिए सेवाग्राम चल पड़े। महादेव भाई ने पूछा-वहाँ कौन-सा इतना महत्वपूर्ण कार्य है? बापू बोले- परचुरे शास्त्री की सेवा का काम तो महत्त्व का है न? महादेव भाई निरुत्तर हो गए। नारायण भाई के शब्दों में बापू के मन में देश की आजादी के प्रश्न पर वाइसराय से बातचीत चलाने और एक कुष्ठरोगी की सेवा करने का महत्त्व समान था। उनकी जीवन-साधना में व्यक्तिगत चित्तशुद्धि और सामाजिक क्रांति-दोनों अविभाज्य और अभिन्न थे। इसीलिए वे एक रोगी की सेवा भी राष्ट्रसेवा जितनी भक्ति से करते। नतीजा यह होता कि वे किसी व्यक्तिगत काम को उठाते तो उस काम को सामाजिक महत्त्व प्राप्त हो जाता और यही उनके व्यक्तित्व के क्षितिजव्यापी होने का राज है। एक अन्य प्रसंग। द्वितीय महायुद्ध शुरू था। वाइसराय के आग्रह पर को उनसे वार्ता के लिए सेवाग्राम से दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन उनको बापू शास्त्रीजी की चिंता बराबर बनी रही। उन्होंने व्यग्रतापूर्वक कहा था-सेवाग्राम में मैं एक रोगी को छोड़कर आया हूँ। मेरा मस्तिष्क भले ही यहाँ है, परंतु मन वहीं है। राष्ट्र की ऐसी विषम परिस्थिति के समय और स्वयं अत्यधिक व्यस्त रहते हुए उनका शास्त्रीजी पर इतना ध्यान था। ऐसी होती उनकी रोगी सेवा और परिचर्या !

संक्षिप्त समाचार

स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का किया अवलोकन

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव और उनके साथ अध्ययन भ्रमण पर आस्ट्रेलिया गई स्वास्थ्य विभाग की टीम आज सिडनी से लगे शहर परममेटा पहुंची। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित उपनगर हैरिस पार्क लिटिल इंडिया के भारतीय मूल के मेयर श्री समीर पाण्डेय ने वहां टीम का स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव और अधिकारियों ने उनके साथ आस्ट्रेलिया में प्राइमरी हेल्थ केयर की स्थिति पर चर्चा की। टीम ने परममेटा से लगे प्राइमरी हेल्थ केयर के भ्रमण के दौरान डॉ. ईश्वर से चर्चा कर ऑस्ट्रेलिया में मुहैया कराई जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। राज्य की टीम ने उन्हें छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने परममेटा के मेयर के साथ चर्चा के दौरान वहां दंत चिकित्सकों एवं नर्सिंग के छात्रों के लिए अवसर, कार्यक्षेत्र एवं संभावनाओं के विकल्पों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डेंटिस्ट और नर्सिंग के विद्यार्थियों को विदेशों में उपलब्ध शोध एवं रोजगार के मौकों के बारे में भी चर्चा की।

बर्खास्त किए गए 16 शिक्षा कर्मियों को मिली हाईकोर्ट से राहत

बिलासपुर। गलत अनुभव प्रमाण पत्र पेश करने के आधार पर बर्खास्त किए गए शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के 16 शिक्षा कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कवर्धा जिले के इन शिक्षाकर्मियों की 17 दिसंबर 2007 को नियुक्ति हुई थी। 27 सितंबर 2008 को उन्हें इस आधार पर सेवा से पृथक कर दिया गया कि उन्होंने गलत अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया है। शासन के आदेश को शिक्षा कर्मियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि अध्यापन अनुभव संबंधी उनके दस्तावेज सही हैं, जिसकी जांच किसी भी सक्षम एजेंसी से कराई जा सकती है। राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट में तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जा सके कि उनके प्रमाणपत्र फर्जी हैं। अवकाश कालीन न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षक कर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए बहाली का आदेश दिया।

अब घर बैठे बनवा सकेंगे राशन-कार्ड मितान योजना की सेवाओं का विस्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर मितान योजना की सेवाओं का विस्तार किया गया है। इसके तहत अब आप घर बैठे ही अपना राशन कार्ड बनवा सकेंगे। राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर 14545 पर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में नागरिक सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। मितान योजना के तहत लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। राज्य सरकार लगातार लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखकर कार्य कर रही है।

फर्नीचर दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

जांजगीर। शिवरीनारायण के बॉम्बे मार्केट स्थित साहू फर्नीचर में बुधवार की रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटे पूरे दुकान में फैल गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। थाना प्रभारी विवेक पाण्डेय ने बताया कि बॉम्बे मार्केट मेन रोड में अशोक साहू का फर्नीचर का दुकान है। बुधवार देर रात को शार्ट सर्किट होने की वजह से साहू फर्नीचर में लाग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे दुकान में फैल गई। खबर पाकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और घरों व दुकानों से पाइप व बाल्टी में पानी भरकर आग बुझाने में लग गए। जब तक फायर बिग्रेड की टीम वहां पहुंचती तब तक आग बुझ चुकी थी। एक घन्टे बाद जांजगीर से फायर ब्रिगेड पहुँची और आग को पूरी तरह बुझाया। इस आगजनी में लाखों का फर्नीचर सामान जलकर खाक हो गया।

रूरल एंड इंडिजेनस नेशनल गेम्स के लिए 242 खिलाड़ियों का हुआ चयन

रायपुर। खेलो इंडिया रूरल एंड इंडिजेनस नेशनल गेम्स 2023 का आयोजन भुवनेश्वर (ओडिशा) में 9 से 12 जून तक होने वाला है। जिसके लिए राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर में खिलाड़ियों का चयन ट्रायल हुआ जिसमें 122 पुरूष तथा 120 महिला खिलाड़ी चयनित हुई। छत्तीसगढ़ आर्चरी संघ के अध्यक्ष कैलाश मुरारका ने बताया कि जनजाति तिरंदाजों के बीच पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 9 से 12 जून तक भुवनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित होने जा रहा है जिसमें 18 राज्यों के लगभग 5000 एथलीट भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ की 10 सदस्य टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेगी जिसके लिए राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर में कोच निलेश गुप्ता और खेल युवा कल्याण विभाग के एक्का के सहयोग से चयन ट्रायल हुआ जिसमें 500 जनजातीय वर्ग के खिलाड़ी शामिल हुए। चयन ट्रायल आयोजित करने का उद्देश्य लोगों में खेल को बढ़ावा देने, उसके बाद उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और उनकी शारीरिक क्षमता उठाने के लिए किया गया।

छत्तीसगढ़ बचाना है, कांग्रेस सरकार हटाना है: साव

भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति संपन्न

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संवेदनहीन है। कोरोना काल में केन्द्र सरकार से अनुमति के लिए पत्र कहां भेजा जाए और आर्थिक सहायता के लिए कहां भेजा जाए यहां तक की इस सरकार के अधिकारियों एवं मंत्रियों तक को पता नहीं। गलत जगह पर पत्र लिखकर केन्द्र सरकार पर आरोप मढ़ने का काम ही यह सरकार साढ़े चार वर्षो तक करती रही एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कोई गंभीर प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं की उनकी रूचि उन्हीं कामों में रही जहां अच्छे खासे कमीशन की गुंजाइस रहती हो कोयला, शराब, रेत, गोठान, ट्रांसफर आदि के घोटालों की लंबी श्रृंखला है। सरकारी खजाने की 50 प्रतिशत राशि को डाका डाला जा रहा था। ऐसे में ईडी की कार्यवाही से भूपेश बघेल का बौखलाना स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार सरकार की रंग-रंग में बसा है।प्रदेश कार्यसमिति के उद्घाटन सत्र का शुभारभ दीप प्रज्वलित कर प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने किया स्वागत पश्चात अपने उद्बोधन में पवन साय ने कहा कि केन्द्र मे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। इन 9 सालों की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाने में चिकित्सा प्रकोष्ठ को अपना सार्थक योगदान देना है। कोविड काल में निष्क्रिय राज्य सरकार की तुलना में केन्द्र की मोदी सरकार ने वैक्शिन, अनाज, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अनुकुल धारा 370 हटाकर एवं राम मंदिर का निर्माण कर कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करने का काम मोदी जी ने किया।

चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विमल चोपड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के 36 के आकड़े ने स्वास्थ्य सेवाओं का कबाड़ कर दिया है। कोविड काल के दौरान भरतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ एवं हेल्थ वालेंटियर्स ने सेवाओं के नये आयाम स्थापित किये जिसकी छाप आज भी सेवा प्राप्त पीड़ितों के दिल में आज भी है। सात मेडिकल कॉलेज की केन्द्र की सौगात को आज भी राज्य की सरकार संभाल ही नहीं पायी है। डॉ. चोपड़ा ने कहा कि कार्य के माध्यम से हमें कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है।

डॉ. चोपड़ा ने ग्रामीण चिकित्सकों के संबंध में सदस्यों की ओर से आयी इस मांग का समर्थन किया कि ग्रामीण चिकित्सक जो बिना डिग्री के वर्षों से ईलाज कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देकर सम्मान पूर्वक प्रैक्टिस करने दिया जाए। हालांकि चुनाव के पूर्व यह वादा कांग्रेस के नेताओं ने किया था जिसे उन्होंने पूरा न करके धोखा किया, वहीं नर्सिंग होम एक्ट से क्लिनिक एवं छोटे नर्सिंग होम को मुक्त किया जाए। ये वादे यदि पूरे नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको पूर्ण करेगी।चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी लोकेश कावड़िया ने संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि एक-एक चिकित्सक 100 से 200 वोटों को प्रभावित कर सकता है।

राजनीतिक प्रस्ताव

प्रदेश में मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के द्वंद्व ने स्वास्थ्य सेवाओं को वेंटीलेटर पर पहुंचा दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली से आमजन त्रस्त है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में एक रात के आई. सी. यू. में अनेक बच्चों की हुए मौत से प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों का विश्वास उठ रहा है। कोरोना काल की बदहाली के बाद अर्थव्यवस्था से सामान्य स्थिति में जाने की उम्मीद थी, परंतु आयुष्मान भारत खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को ट्रस्ट मोड को चलाने के बाद अब अस्पताल के भुगतान में हो रहे विलंब का प्रभाव मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है, और अनुबंधित अस्पतालों से इलाज में मनाही हो रही है। इसके साथ साथ अनेक आवश्यक बिमारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से सरकार ने हटा दिया जिसके कारण गरीब जनता को बेहद परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। नर्सिंग होम एक्ट में सुधार की बात कह कर सत्ता में आने वाली सरकार ने इसमें किसी प्रकार की राहत न देकर वादाखिलाफी की है। पर्यावरण एवं अग्निशमन की एनओसी के नाम पर प्रदेश में माफिया कार्य कर रहा है। 30, 40 बिस्तर के छोटे अस्पतालों के संचालन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने प्रयास भी चार में सालों में नक्कार खाने में तूती की तरह ही रहे है।

फ्लाई ओवर निर्माण के चलते रूट डायवर्ट

- **दुर्ग से रायपुर जाने वाले यात्रियों को घर से निकलना पड़ेगा जल्दी**

दुर्ग। रायपुर से दुर्ग के बीच नेशनल हाइवे 53 में 3 अलग-अलग जगहों पर फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके चलते डबरापारा तिराहा निर्माणधीन ओवर ब्रिज के नीचे पाईप लाईन का कार्य किया जाना है। इस कार्य के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार से सोमवार तक तीन दिनों के लिए काम से बचाने के लिए रूट डायवर्ट करने का फैसला लिया है। इस दौरान जो लोग दुर्ग से रायपुर जाना चाह रहे हैं वो उतई, सेलूद, फण्डा, मोतीपुर अम्लेश्वर मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि डबरापारा तिराहा में निर्माणाधीन फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे आगामी बरसात को देखते हुए पाईप लाईन का कार्य किया जा रहा है। इसके कारण शनिवार और रविवार को दुर्ग से रायपुर मार्ग डबरापारा के पास बंद रहेगा। इस दौरान लाइट हैवी वाहनों को परिवर्तित मार्ग खुर्सीपार चौक से केनाल रोड होते हुए और हथखोज से उमदा भिलाई 3 मार्ग का उपयोग किए जाएगा। इसके साथ ही हल्के वाहनों को केनाल रोड के जीरो पाइंट से डबरापारा तिराहा से निकाला जाएगा। वही सोमवार के दिन रायपुर से दुर्ग की तरफ के लेन में पाइप लाइन का कार्य किया जाएगा। इसके चलते रायपुर से दुर्ग आने वाले वाहनों को डबरापारा मंदिर कटिंग के सामने से विपरीत दिशा से निकाला जाएगा। खुर्सीपार हॉस्पिटल के पास से वापस अपनी लेन में आ जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 जून को प्रदेश में पांच लाख लोग लेंगे शपथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 01 जून को एक दिन में पांच लाख लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लेंगे। प्रदेश में मिशन लाईफ कार्यक्रम के अंतर्गत लाईफ स्टाईल फॉर इन्वायरमेंट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में 01 जून को पर्यावरण संरक्षण के लिये शपथ का कार्यक्रम रखा गया है।

लाईफ प्लेज के अंतर्गत पूरे राज्य में एक साथ पांच लाख लोगों द्वारा प्लेज लिये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि व्यापक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता लायी जा सके। एक ही दिन में पांच लाख लोग शपथ लेकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता दर्शायेंगे। शपथ हिन्दी या अंग्रेजी में समूह या व्यक्तिगत रूप से लेकर उसका वीडियो व फोटो वॉट्सएप नम्बर +91-7415781776, +91-9109028361, +91-7415796619 पर 01 जून को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक भेजी जा सकेगी।

मोबाइल फोन के लिए बहाया 21 लाख लीटर पानी, खाद्य निरीक्षक निलंबित

- **जल संसाधन विभाग के पखांजूर के अनुविभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस**

कांकेर। कांकेर जिले के पखांजूर तहसील के परलकोट जलाशय में गिरा मोबाइल ढूंढने के लिए पानी बहाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संबंधित खाद्य निरीक्षक को कलेक्टर कांकेर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में पखांजूर में पदस्थ जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जिला उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर पखांजूर में पदस्थ खाद्य निरीक्षक श्री राजेश विश्वास को आज तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि खाद्य निरीक्षक पखांजूर श्री राजेश विश्वास द्वारा परलकोट जलाशय, पखांजूर में उनका मोबाईल पानी में गिर जाने के कारण, मोबाईल ढूंढने के लिए 21 मई 2023 से लगातार 04 दिनों तक परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वाय के बीच लगभग 21 लाख लीटर पानी डीजल पंप के द्वारा बहा दिया गया, यह जानकारी मिलने पर इस घटना के संबंध में 26 मई 2023 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर से प्रतिवेदन लिया गया, प्रतिवेदन अनुसार श्री राजेश विश्वास खाद्य निरीक्षक, पखांजूर द्वारा परलकोट जलाशय पखांजूर में अपना मोबाईल ढूंढने के लिए बिना अनुमति के जलाशय के वेस्ट वियर का 41104 क्यूबिक मीटर पानी खाली कराया गया है।

प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा श्री राजेश विश्वास खाद्य निरीक्षक, पखांजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि अपना मोबाईल ढूंढने के लिए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना परलकोट जलाशय से भीषण गर्मी में लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा देना, उनके अशोभनीय आचरण का द्योतक है, जो अस्वीकार्य है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

हमर लैब्स ने बढ़ाई जांच की सुविधा अब तक 57.46 लाख जांच

- **जिला अस्पतालों के हमर लैब में 120 और सीएचसी के लैब में 60 तरह की जांच**

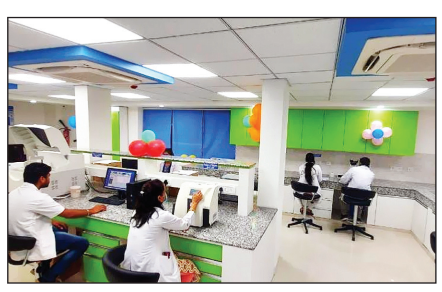

रायपुर। प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में संचालित हमर लैब से मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही अनेक तरह की जांच की सुविधाएं मिल रही हैं। हमर लैब वाले जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधाओं में खासी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित जिला अस्पतालों के हमर लैब में 120 तरह की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के हमर लैब में 60 प्रकार की जांच की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य के 16 हमर लैब में 1 अप्रैल 2022 से अब तक कुल 57 लाख 46 हजार पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जांच की गई हैं।

राज्य का पहला हमर लैब फरवरी-2020 में रायपुर जिला चिकित्सालय में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 2022 से अब तक यहां सात लाख 48 हजार 128 जांचें की जा चुकी हैं। सुदूर वनांचल बीजापुर के जिला अस्पताल के हमर लैब में छह लाख 96 हजार 357, जगदलपुर जिला अस्पताल के हमर लैब में छह लाख 55 हजार 812, कांकेर जिला अस्पताल में छह लाख 52 हजार 698, दुर्ग जिला अस्पताल में पांच लाख 48 हजार 951, बालोद जिला अस्पताल में चार लाख 63 हजार 330, सुकमा जिला अस्पताल में तीन लाख 69 हजार 621, बलौदाबाजार जिला अस्पताल में तीन लाख चार हजार 028, राजनांदगांव जिला अस्पताल में दो लाख 38 हजार 195, कोंडागांव जिला अस्पताल में दो लाख 12 हजार 439 और बलरामपुर जिला अस्पताल के हमर लैब में इस दौरान एक लाख 74 हजार 589 जांचें की गई हैं। पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हमर लैब में अप्रैल-2022 से अब तक दो लाख 23 हजार 356 जांचें की गई हैं। इस दौरान मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हमर लैब में एक लाख 12 हजार 839, पलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 70 हजार 052 और खरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 हजार 603 जांचें की गई हैं। अंबिकापुर स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में भी इस वर्ष 6 फरवरी से हमर लैब संचालित है।

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं के संरक्षण व संवर्धन का करेगी कार्य: भगत

- **हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता को करेंगे जागरूक**

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय, महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मनोनित सदस्यों और प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण हेतु परिषद के गठन के लिए धन्वाद दिया। खाद्य मंत्री श्री भगत ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन कर उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। हम सबको सहभागिता के साथ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है।

मंत्री श्री भगत ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण का दायित्व राज्य शासन का होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में सलाह देने के लिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से कहा कि आप राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में उपभोक्ताओं के मूलभूत हितों से जुड़े सभी आवश्यक कार्य करेंगे। राज्य परिषद् की बैठक में उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में राज्य शासन को सलाह देने के लिए परिषद् के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् राज्य में उपभोक्ता हितों के संबंध में समय-समय पर राज्य शासन को सलाह देती रहेगी।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, विशेष सचिव श्री मनोज सोनी, परिषद के मनोनित प्रतिनिधियों में श्री नवीन श्रीवास्तव, श्री शशि भगत, श्री प्रमोद गुप्ता, श्रीमती शशि प्रभा गायकवाड़, श्री सुरेश गोयल, श्री सुरेश अग्रवाल, श्री अभिषेक सिंह सहित स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग एवं वाणिज्यिकर, कृषि, समाज कल्याण, राज्य विद्युत वितरण कंपनी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ व्यापारिक संगठन, लीड बैंक छत्तीसगढ़ राज्य, प्रशासक दूर संचार, रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सहित राज्य सरकार द्वारा नामांकित उपभोक्ता संरक्षण के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सत्रह राज्यों के अधिकारियों ने नरवा विकास का स्थल में जाकर किया अवलोकन

- **दल द्वारा लघु वनोपजों के प्रसंस्करण केन्द्र दुगली का भी भ्रमण**

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में राजधानी में 23 मई से मृदा एवं जल संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के उच्चाधिकारियों के दल ने स्थल भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान दल द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा विकास योजना के तहत धमतरी वन मंडल के दक्षिण सिंगपुर परिक्षेत्र अंतर्गत पम्पार नाला के पुर्नोद्धार कार्य सहित भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का विस्तार से अवलोकन किया गया।

दल ने लघु वनोपजों के प्रसंस्करण केन्द्र दुगली का भी भ्रमण कर वहां कार्यरत समूह की महिलाओं से चर्चा की। दल में 17 विभिन्न राज्यों एवं 02 संघ शासित प्रदेश के विभागीय उच्चाधिकारी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में 23 से 25 मई तक रायपुर में वन क्षेत्र के अंदर बहने वाले नदी-नालों के जीर्णोद्धार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण के उपाय तथा लघु वनोपजों के सतत प्रबंधन हेतु तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया।

भ्रमण के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने दल को बताया कि छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा जी.आई.एस. टूल्स और अन्य तकनीकों का प्रयोग करते हुये वन क्षेत्रों में नरवा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नरवा का डी.पी.आर. तैयार कर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में नरवा विकास योजनांतर्गत वन क्षेत्रों में कराए जा रहे भू-जल संरक्षण के कार्य से अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इससे वनों में मिट्टी के कटाव में कमी हो रही है।

दल को बताया गया कि पम्पार नाला में भू-जल संवर्धन संबंधी निर्मित संरचनाओं में ब्रश वुड चेक डेम-44, लूज बोल्डर चेक डेम-68, ईजीपी-3, गेबियन संरचना-3, टी.एफ.एम.-188, सी.एस.बी.-24, डायवर्सन ड्रेन-1, एम.पी.टी.-2, पॉंड-2, परकोलेशन टैंक-1, एस.सी.टी., सी.सी.टी.-409, डाइक पडल्ड-2, वाट-35, ईसीबी- 26, एस.डी.-1 सहित कुल 809 संरचनाएं शामिल हैं। इस दौरान केन्द्रीय वन विभाग द्वारा देश के अन्य सभी राज्यों को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाई गई प्रणाली का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान नरवा विकास योजना अंतर्गत नालों में किये जा रहे उपचार एवं निर्मित संरचनाओं के बारे में चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी भ्रमण दल को दिया गया।

दल में 17 विभिन्न राज्यों एवं 02 संघ शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) शामिल थे, इनमें श्री कैलाश चन्द्र मीणा राजस्थान, श्री बसता राजकुमार पंजाब, श्री पी. पी. सिंघ उत्तर प्रदेश, मनीबी मित्तल उत्तर प्रदेश, डॉ. सौरव घोष फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, श्री रमन कांत मिश्रा पंजाब, श्री जगदीश चंद्र हरियाणा श्री विवेक सक्सेना आईआरओ लखनऊ. श्री शैलेष टेंभुलकर महाराष्ट्र, श्री पंकज गर्ग महाराष्ट्र श्री अरविंद सिंघ बिहार, डॉ के. रविचन्द्रन आईआईएफएम भोपाल, श्री बी आनन्द बाबु एमएफपी फेडरेशन, श्री लोकेश जयसवाल तेलंगाना श्री महेन्द्र सिंघ धाकर मध्यप्रदेश, श्री सुधांशु गुप्ता तमिलनाडु डॉ योगेश के दुबे भोपाल, श्री महेश चंद गुप्ता राजस्थान श्री संतोष विजय शर्मा उत्तराखण्ड, श्रीमती समीता राजोरा मध्यप्रदेश, श्री एस.एस. रासैली उत्तराखण्ड थे।

अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना...

28 मई को देश को नया संसद भवन मिल जाएगा और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं।ब्रिटिश राज में बना संसद भवन 97 वर्षों तक भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना और अब वह बूढ़ा हो चुका है। इमारत कमजोर हो गई हैऔर सुविधाएं कम पड़ गई हैं।पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर, 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (अनुसूचित जाति वर्ग) थे तब उन्हें ही कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया था और अब नया संसद भवन बनकर तैयार है।अब मौजूदा राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (अनुसूचित जनजाति वर्ग) हैं पर समारोह में उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया है,विपक्ष इसे अजा/अजजा वर्ग का अपमान ठहरा रहा है?भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ के लिये एक संसद होगी,जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी,राष्ट्रपति,संसद का अनिवार्य अंग है,ज़ब नये संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो राष्ट्रपति को ही आमंत्रित नही करना,लोकार्पण नहीं कराना संविधान की अवहेलना है।दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहलाने वाले भारत में राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है,जिसकेआदेश के बिना संसद का सत्र भी नहीं बुलाया जा सकता,किसी क़ानून या बिल को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाएं। तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा है कि नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए,न कि प्रधानमंत्री को।अब तो कांग्रेस सहित 21 राजनीतिक दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। खैर ,विवाद तारीख को लेकर भी है। 28 मई, 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 150वीं जयंती है वहीं इसी दिन देश के पहले पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू का अंतिम संस्कार भी हुआ था।सावरकर केंद्र में सत्तारूढ़ दल भाजपा के वैचारिक प्रेरणा स्रोत हैं। 26 मई, 2023 को मोदी सरकार के नौ साल पूरे हो गये हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इधर प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं तो राष्ट्रपति विधायिका के अध्यक्ष होते हैं। बल्कि संसद का निर्माण ही लोस,राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। विरोधी इसी का हवाला देकर पीएम की जगह राष्ट्रपति से नये संसद भवन के उद्घाटन की मांग कर रहे हैं,छग के सीएम भूपेश बघेल और देश के प्रमुख आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने भी राष्ट्रपति से नये संसद भवन का उद्घाटन कराने का समर्थन किया है।मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन वाईसराय ने किया था।1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। इस कारण भारत में संसद भवन के उद्घाटन का सौभाग्य उन्हें ही हाथ लगा।18 जनवरी, 1927 को लॉर्ड इरविन ने मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन किया था। तब उसे %हाउस ऑफ पार्लियामेंट% कहा गया। इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी।

'सेंगोल' यानि राजदण्ड, राजशाही का उदय.....?

अंग्रेजों के जिस राजदंड को पंडित नेहरू ने इलाहाबाद संग्रहालय में दफना दिया था,उसे भारतीय संसद में स्थापित किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में राजदंड क्यों स्थापित किया जाएगा..? अगर राजदंड स्थापित होगा तो राजा कौन होगा...? क्या मध्ययुगीन राजशाही वापस आने वाली है..? गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नई संसद में राजदंड स्थापित किया जाएगा। स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा,यह भी बताया कि जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इसे पंडित नेहरू को सौंपा था। सत्ता हस्तांरण के समय जिस राजदंड को अंग्रेजों ने नेहरू को सौंपा,वह इलाहाबाद के संग्रहालय में क्यों रखा था...? क्योंकि राजदंड राजा की शक्ति का प्रतीक है। उस समय यह अंग्रेजों की राजशाही के प्रतीक के रूप में नेहरू को सौंपा गया, जिसका मतलब हुआ कि अब सत्ता भारत के हाथों में सौंपी जाती है।तब भारत में लोकतंत्र नहीं था। उसके बाद भारत लोकतंत्र बनाऔर उस "राजदंड" को नेहरू ने संग्रहालय में रखवा दिया। यह "सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक" था। उस समय सत्ता एक साम्राज्य से हस्तांरित हुई जिसे भारत की जनता ने लड़कर छीनी थी। आज कौन सा सत्ता हस्तांतरण हो रहा है?अभी कौन किसे सत्ता सौंप रहा है...?

छग में सीमा तय, पर आकाश तो हमारा है ...?

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने बयानों के साथ ही शौकीन अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। बात चाहें उनके पहनावे की हो या सफर की,सभी जगह वो एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। छ्ग के सीएम तो वो नहीं बन सके....? पर वे कहते हैं कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती है..? सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह पैराग्लाइडिंग और पैराजंपिंग करते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि टीएस सिंहदेव इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने स्काई डाइविंग का आनंद लिया।मंत्री ने हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर रोमांचक स्काई डाइविंग काआनंद लिया। उन्होंने ऐसा करके यह साबित कर दिया कि एडवेंचर में उम्र कोई मायने नहीं रखती। सिंहदेव के अपने ट्विटर वीडियों में दिख रहा है कि वह हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और फिर जमीन पर आते हैं। इस दौरान गाइड के सवाल पर कहते हैं कि यह उनके लिए बहुत सुखद अनुभव है, जिसे वह बार-बार करना चाहेंगे। सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा कि "आकाश की पहुंच की कोई सीमा नहीं होती"। मेरे पास स्काइडाइविंग करने का अविश्वसनीय अवसर था और यह वास्तव में एक असाधारण साहसिक कार्य था। यह एक बेहद अच्छा अनुभव था।

छग में वनमैन आर्मी भाई बृजमोहन....

छ्ग में भाजपा के बड़े तथा वरिष्ठ नेताओं में बृजमोहन अग्रवाल की गिनती होती है। रायपुर विधानसभा के वे अपराजेय योद्धा हैं, उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं हारा है? वो तो नंदकुमार साय (आजकल कॉंग्रेस में)को छ्ग का पहला नेता प्रतिपक्ष बनाने के विरोध के चलते नरेंद्र मोदी की नजर में आ गये हैं,खैर कर्नाटक हार के बाद अब छ्ग में अगले विस चुनाव में मोदी के साथ डॉ रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल को भी प्रमुख चेहरा बनाने की चर्चा शुरू हो गई है.?आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनी यह कथित तस्वीर विधायक बृजमोहन अग्रवाल की है जो मीडिया में वायरल है वाकई में अगर सोल्जर होते तो ऐसे ही दिखते बृजमोहन.....?

जेल में व्हीआईपी के लिये आरक्षण.... ?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में व्ही आईपी के लिये बैरकों का आरक्षण कर दिया गया है।बैरक नंबर दो की पहचान तो व्हीआइपी सेल के रूप में हो गई है। हाईप्रोफाइल आरोपितों के लिए बैरक नंबर एक से पांच को फिलहाल आरक्षित कर दिया गया है। महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज हों या फिर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह, सभी को बैरक नंबर दो में रखा गया था। अब ईडी की गिरफ्त में आए आईएएस समीर बिश्नोई और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को भी बैरक नंबर दो और तीन में रखा गया है। अब तो रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर भी यहीं पहुँच चुके हैं।उन्हें बैरक नंबर 5 में रखा गया है।वहीं कुछ लोगों का भी जल्दी ही जेल में पहुंचना तय है,इन बैरकों की यह खासियत है कि यहां आरोपियों को अकेले रहने दिया जाता है। इनको सुबह अखबार भी दिया जाता है। यही नहीं, यहां अलग से बाथरुम की व्यवस्था है और यह बैरक आम कैदियों के बैरक से काफी दूर अलग बनाया गया है।इधर चर्चित अफसर सौम्या चौरसिया को महिला जेल में एक अलग बैरक में रखा गया हैऔर एक महिला वार्डन उनके साथ अटैच है ?

और अब बस

- झिरमघाटी नक्सली वारदात में अब क़वासी लखमा,अमित जोगी,डॉ रमन सिंह, मुकेश गुप्ता आदि के नार्को टेस्ट की मांग जोर पकड़ रही है।
- छ्ग में 15 पुलिस अधिक्षकों का तबादला हो गया है वहीं 4आईजी सहित कुछ आईपीएस के प्रभार में जल्दी बदलाव हो सकता है।
- जैसे प्रधानमंत्री का रास्ता उप्र से होकर गुजरता है वैसे ही छ्ग की सरकार का रास्ता बस्तर से खुलता है।
- नेता प्रतिपक्ष भले ही नारायण चंदेल बन गये हैं पर धरमलाल कौशिक अभी भी फार्म में हैं?

जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लैक लिस्ट

रायपुर। जल जीवन मिशन के संचालक द्वारा मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर को राज्य के समस्त जिलों में जल जीवन मिशन से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। साथ ही कोई निविदाकार यदि मेसर्स बंसल इन्फ्रास्ट्रक्चर के अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग ज्वाईंट वेंचर के रूप में करते हैं तो उन्हें भी अपात्र करने के निर्देश दिए गए हैं।

जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने बताया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यालय में उपलब्ध निविदा दस्तावेजों के अनुसार मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा पूर्व आमंत्रित मल्टीविलेज स्कीम की 12 निविदाओं में 08 ठेकेदारों के साथ ज्वाइंट वेंचर किया गया है। उक्त निविदाओं निविदाकारों द्वारा शपथ पत्र के साथ जो मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं, प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने की आशंका के कारण उन अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए E&ecutive Engineer, P.H. Division संबलपुर एवं भवानीपटना, ओडिशा को विशेष वाहक द्वारा भेजते हुए इसकी सूचना मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, ओडिशा को दी गई।

कार्यपालन अभियंता, सम्बलपुर, ओडिशा के द्वारा अवगत कराया गया है कि मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा मल्टीविलेज स्किम के निविदाओं में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र- "Construction of Balance work for Supply of Drinking Water to Rairakhol & its adjoining areas from River Mahanadi at Kiakata" उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा निविदा दस्तावेजों में फर्जी एवं कूटरचित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो अत्यंत गंभीर अपराधिक कृत्य है। इस संबंध में जल जीवन मिशन द्वारा मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।

इन फर्मों को दिया गया है नोटिसः जल जीवन मिशन अंतर्गत ठेकेदार मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर (पंजीयन क्र. ष्ठत्नद्रक्र3372) के द्वारा मल्टीविलेज योजनाओं की निविदाओं में फर्जी पेपर लगाकर ज्वाईंट वेंचर्स दिये जा रहे हैं और भारी भरकम राशि की वसूली किये जाने की शिकायत भ्रष्टाचार निवारण समिति, रायपुर द्वारा प्राप्त शिकायती पत्र 12 मई 2023 के अनुसार मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जल जीवन मिशन की MVS योजनाओं जैसे - मंगलापासीद MVS (मे. गणेश कंस्ट्रक्शन), बिटकुली MVS (मे.संजय अग्रवाल), जेवरा-सिरसा MVS (मे. वेस्ट इंडिया कंपनी), कनेरी MVS (मे. सूर्या इंटरनेशनल), खरवाय MVS(मे. रेखचंद अग्रवाल), गिरौदपुरी MVS (मे. रत्ना खनिज उद्योग), समोदा-अछोला MVS (मे. जय बंजरंग कंस्ट्रक्शन), अगमधाम MVS(मे. राधेश्याम अग्रवाल) आदि लगभग सभी निविदाओं में ज्वाईंट वेंचर देकर निविदा में सांठ-गांठ किया किया गया है। इन सभी ठेकेदारों को भी नोटिस जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मोबाइल के लिए जलाशय खाली कराने के पीछे खाद्य घोटालाः चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बस्तर के पखांजूर इलाके में मोबाइल फोन खोजने के लिए 21 लाख लीटर पानी बहाकर जलाशय खाली करने वाले खाद्य निरीक्षक को निलंबित किये जाने को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि उसे बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही उस खाद्य निरीक्षक के उस तथाकथित महत्वपूर्ण मोबाइल की गंभीरता से जांच करनी चाहिए कि उसमें ऐसा क्या था, जिसके लिए उसने बिना भय के इतना पानी बहा दिया, जिससे डेढ़ हजार एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी और इस भीषण गर्मी के समय निस्तारी पानी उपलब्ध कराया जा सकता था।नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़बो छत्तीसगढ़ की यह एक बानगी है। भूपेश बघेल ने ऐसा नवा छत्तीसगढ़ गढ़ दिया है, जिसमें भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है और भ्रष्टाचारी अपना करामाती मोबाइल खोजने के लिए बांध खाली कर रहे हैं।

फूड इंस्पेक्टर की गलती पर सरकार को घेरना भाजपा का राजनैतिक दिवालियापनः कांग्रेस

रायपुर। पखांजूर के जलाशय में एक अधिकारी की गलती पर भाजपा नेताओं की बयानबाजी भाजपा की अवसरवादिता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर परलकोट जलाशय में पानी बर्बाद करने वाले दोषी फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गयी है तथा अन्य जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी नोटिस जारी की गयी जो और लोग इस कृत्य के लिये जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा इस मामले में जो बयानबाजी कर रहे भाजपा नेता जान ले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का राज है जो गलती करता है उस पर कड़ी कार्यवाही की जाती है, दोषियों को बख्शा नहीं जाता और न ही दोषियों को सरकारी संरक्षण मिलता है। रमन राज में अधिकारी डीएमएफ के पैसे से अपने बंगले में स्वीमिंग पूल बनवाते थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री, वनमंत्री उस पर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं दिखाते थे। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि कैसे रमन सरकार में राजधानी रायपुर से मात्र 35 किमी दूर स्थित पेंड्रावन जलाशय को एक निजी कंपनी को बेच दिया गया था।

महिलाओं के साथ हुई बर्बरता शर्मनाकः भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाये रखने में पूरी तरह नाकाम रही प्रदेश सरकार के कारिंदे भी अब बर्बरता का शर्मनाक उदाहरण पेश कर रहे हैं। श्री सिंहदेव ने सरगुजा के सूरजपुर स्थित ग्राम तिलसिवाँ में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ की गई बर्बरता को प्रदेश के लिए कलंक बताया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंहदेव ने तिलसिवां ग्राम में घटित इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला देकर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या इसी स्मार्ट पुलिसिंग के दावे करके प्रदेश सरकार इठला रही है? क्या कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बनकर महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता के लिए खुले घूम रहे हैं? श्री सिंहदेव ने इस बर्बरता के वायरल वीडियो का जिक्र कर बताया कि ग्राम तिलसिवाँ में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं में से पुलिस ने सात महिलाओं को पहले तो गिरफ्तार किया और फिर उनसे बर्बरता करके हुए सारी हदें लांघ दीं। इस पूरे मामले के वायरल रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिस कर्मी ने महिला के बाल पकड़कर घसीटा और नीचे गिराया, फिर महिला की पीठ पर जूते पहने हुए ही जमकर लात मारी, जिससे महिला बेसुध हो गई। एक ओर महिला सशक्तीकरण के ढिंढोरे पीटती प्रदेश सरकार अपने ही मुँह मियाँ मिठ्ठू बनते फिर रही है।

नये संसद भवन के उद्घाटन से राष्ट्रपति को दूर रखना आदिवासियों के अपमानः ठाकुर

रायपुर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक धरमलाल कौशिक के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय भी आमंत्रित थे लेकिन वो निजी कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाये थे और उक्त कार्यक्रम में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी मंच में विराजमान थे ऐसे में भाजपा के नेता संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने और राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन नहीं कराए जाने के बचाव में कांग्रेस पर आरोप लगाकर आदिवासी वर्ग के साथ हो रहे अन्याय एवं अपमान के महापाप से बच नहीं सकते।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदीभक्ति में लीन भाजपा नेताओं के आंखों में काली पट्टी बंधी वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के नेता छपास रोग से ग्रसित है और छपने और दिखने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं किसी का भी अपमान कर सकते हैं मर्यादाओं को तार-तार कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी समाज की महिला का अपमान भाजपा की सरकार कर रही है।

झीरम नरसंहार मामले में भूपेश बघेल का नार्को टेस्ट होः गागड़ा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने झीरम घाटी नरसंहार मामले पर कहा कि इस मामले में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नार्को टेस्ट कराये जाने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही वे सारे तथ्य सार्वजनिक हो सकेंगे, जिनको अपनी जेब में रखने का दावा करके दशक भर से मुख्यमंत्री बघेल कर रहे हैं।भाजपा नेता व पूर्व मंत्री श्री गागड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल झीरम मामले को न्याय के बिंदु तक पहुंचाने के बजाय इसे अपनी राजनीति के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री बघेल ने अब तक वे सबूत और तथ्य सार्वजनिक क्यों नहीं किए हैं जो इस जघन्य हत्याकांड की जाँच और शहीदों के परिजनों को न्याय की दहलीज तक पहुँचा सकें। श्री गागड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री कवासी लखमा इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनके घटनास्थल से मोटर साइकिल से सुरक्षित बच निकलने पर भी तब से लेकर अब तक सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद खुद डॉ. चरणदास महंत ने काफी पूछताछ की थी और उनकी तलाशी भी ली थी। अब मुख्यमंत्री बघेल इधर-उधर की बातें करके इस मामले में भी सस्ती राजनीति कर रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री बघेल झीरम के किन आरोपियों को बचाने की कवायद कर रहे हैं?भाजपा नेता व पूर्व मंत्री श्री गागड़ा ने कहा कि अब मुख्यमंत्री बघले खुद भी दबी जुबान से मंत्री लखमा के नार्को टेस्ट की बात कर रहे है।

प्रदेश में अब तक तीन चौथाई तेंदूपत्ता का संग्रहण पूर्ण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 के दौरान अब तक 12 लाख 27 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है, जो लक्ष्य के 75 प्रतिशत के करीब है। ज्ञातव्य है कि राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16 लाख 72 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में वनांचल के आदिवासी-वनवासियों द्वारा तेंदूपत्ता का संग्रहण कार्य तेजी से जारी है।

- वन मंडल सुकमा में लक्ष्य से अधिक 110 प्रतिशत तेन्दूपत्ता का संग्रहण
- 16.72 लाख मानक बोरा के लक्ष्य के विरूद्ध 12.27 लाख मानक बोरा संग्रहित

प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्री अनिल राय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक संग्रहित मात्रा में से वनमण्डल बीजापुर में 73 हजार 99 मानक बोरा तथा सुकमा में एक लाख 19 हजार 243 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण शामिल है। इनमें वनमंडल सुकमा में लक्ष्य एक लाख 8 हजार मानक बोरा के विरूद्ध एक लाख 19 हजार 243 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य का 110 प्रतिशत है। इसी तरह वनमण्डल दंतेवाड़ा में 15 हजार 630 मानक बोरा, जगदलपुर में 20 हजार 971 मानक बोरा, दक्षिण कोण्डागांव में 18 हजार 608 मानक बोरा तथा केशकाल में 24 हजार 963 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है। वनमण्डल नारायणपुर में 18 हजार 485 मानक बोरा, पूर्व भानुप्रतापपुर में 90 हजार 649 मानक बोरा, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 32 हजार 196 मानक बोरा, तथा कांकेर में 33 हजार 342 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है।इसी तरह वनमण्डल राजनांदगांव में 60 हजार 569 मानक बोरा, खैरागढ़ में 24 हजार 49 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है। बालोद में 19 हजार 17 मानक बोरा, कवर्धा में 32 हजार 97 मानक बोरा, वनमण्डल धमतरी में 20 हजार 584 मानक बोरा, गरियाबंद में 77 हजार 570 मानक बोरा, महासमुंद 70 हजार 78 मानक बोरा तथा बलौदाबाजार 15 हजार 949 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है।

वनमण्डल बिलासपुर में 25 हजार 200 मानक बोरा, मरवाही 10 हजार 683 मानक बोरा, जांजगीर-चांपा में 6 हजार 881 मानक बोरा, रायगढ़ में 49 हजार 23 मानक बोरा, धरमजयगढ़ में 70 हजार 861 मानक बोरा, कोरबा में 43 हजार 705 मानक बोरा तथा कटघोरा में 56 हजार 844 मानक बोरा का संग्रहण हुआ है। इसी तरह वनमण्डल जशपुर में 27 हजार 291 मानक बोरा, मनेन्द्रगढ़ 22 हजार 530 मानक बोरा, कोरिया में 15 हजार 626 और सरगुजा में 20 हजार 595 मानक बोरा, बलरामपुर में 71 हजार 156 मानक बोरा, सूरजपुर में 39 हजार 148 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है।

ग्रामीण औद्योगिक पार्क गोड़बहाल में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र की हुई स्थापना

रायपुर। दूध के सही दाम न मिलने से महासमुंद जिले के गोड़बहाल गांव में पशुपालन लगभग खत्म हो रहा था, लेकिन वहां के सरपंच व ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। सरपंच श्री सादराम पटेल ने पहल कर पांच समिति बनाया, दूध से बनने वाले उत्पादों के लिए कुछ ग्रामीणों को ट्रेनिंग दिलायी और आज ये सभी पनीर, खोआ, दही, पेड़ा और राबड़ी को बेचकर अच्छी कमाई कर रहे है। पिथौरा में दुग्ध उत्पाद विक्रय केंद्र नाम से दुकान भी डाली है। गोड़बहाल गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया। इसके अलावा माटीकला, पेवर ब्लॉक के साथ महिला समूह वर्णित कम्पोस्ट के साथ ही स्थानीय बाज़ार की मांग अनुसार मसाले, पापड़, अचार, आदि सामग्रिया का उत्पादन कर अपनी आमदनी में अतिरिक्त इजाफा कर रही है।

महासमुंद जिले के पिथौरा से तक़रीबन आठ किलोमीटर दूर गोड़बहाल गाँव में पुरुषों ने पाँच सहकारी समिति द्वारा बनायी। एक समिति में 70 ग्रामीण जुड़े है। इस समिति से जुड़े गोड़बहाल गाँव के ग्रामीण बताते हैं, हमारे गाँव में गाय भैस का दूध समिति अधिक दाम में ख़रीद रही है। समिति से जुड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वहीं दुग्ध उत्पाद सामग्री जो शुद्ध पनीर बेच रहे वो 340 रुपए किलो, खोवा 320, पेड़ा 360, दही 70 और रबड़ी 340 रुपये किलो की दर से बेच रहे है। माह में सब खर्च के बाद 70 से 80 हजार का मुनाफ़ा हो रहा है। कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने डीएमएफ मद से समिति को 2000 लीटर का बल्क मिल्क कूलर उपलब्ध कराया गया है। इससे दूध ख़राब होने की चिंता से मुक्ति मिल गयी है। बिजली अचानक चली जाने पर यह कई घंटे काम करता है और दूध ख़राब नहीं होता है। कलेक्टर ने कहा है कि ज़िले की अधिकांश आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। दुग्ध उत्पादन को लेकर स्थिति बहुत अधिक मजबूत हुई है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.